● वर्ष-3
● अंक-189
रायपुर, शनिवार
16 मार्च 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› कई फायदे सिंगलहुड के

मुख्यमंत्री ने लिये पांच अहम फैसले

सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा चार फीसदी, पेंशनरों को भी होगा लाभ

पत्रकारों के खिलाफ किये गये कथित झूठे मुकदमों एवं उत्पीड़न के मामलों में न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

सातवें वेतनमान के एरियर्स के तिम किश्त की राशि भी मिलेगी

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित की गई समिति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारी-कर्मचारियों तथा मीडियाबंधुओं के हित में पांच अहम फैसले लिये। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा।

महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी। राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही

मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी।

ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्यौहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे।

पत्रकारों को न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा।

अब महंगाई भत्ता हुआ 46 प्रतिशत

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।

सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त भी मिलेगी

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।

हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा

मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा।

केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना धुआंधार दौरे पर मोदी

जनसभाओं के जरिए दक्षिण के दुर्ग को भेदने का जिम्मा खुद उठाया

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 14 मार्च की तारीख खबरों के लिहाज से काफी व्यस्ताओं वाला रहा जिसमें दो नए चुनाव आयुक्तों का चयन और चुनावी बांड योजना के संबंध में जानकारी जारी की गई। वहीं राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने चुनावी अभियान पर पूरा फोकस है। केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु तीन महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्य हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बढ़ते प्रयासों के तहत दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी कम से कम 19 मार्च तक विभिन्न रोड शो करने की उम्मीद है। यही कारण है कि भाजपा को दक्षिण में कड़ी मेहनत करने के लिए पीएम मोदी की जरूरत है।

15 से 19 मार्च तक प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में ही रहेंगे। पीएम मोदी दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए

15 मार्च को केरल के पलक्कड़ का दौरा करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद, 17 मार्च को मोदी भाजपा उम्मीदवार और कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी के लिए समर्थन जुटाने के लिए पथानामथिट्टा का एक और दौरा करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पलक्कड़ पहुंचने पर मोदी एक विशाल रोड शो करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी और कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता पद्मजा वेणुगोपाल भी एनडीए के लोकसभा सांसद वी मुरलीधरन, अनिल के एंटनी, शोभा सुरेंद्रन के साथ बैठक में मौजूद रहेंगी। पिछले साल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के साथ असहमति के कारण अन्नाद्रमुक के एनडीए छोड़ने के बाद पहली बार, भाजपा तमिलनाडु में किसी सहयोगी के बिना है। पीएम मोदी इस साल राज्य के अपने पांचवें दौरे के दौरान कन्नियाकुमारी में चुनाव प्रचार करेंगे।

तेलंगाना से शुरुआत- आज, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए समर्थन हासिल करने के लिए तेलंगाना का दौरा करके अपना अथक अभियान दौरा जारी रखेंगे। उनका आज शाम मल्काजगिरी चौरास्ता में एक रोड शो के लिए बेगमपेट पहुंचने का कार्यक्रम है। उनके साथ पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार एटाला राजेंदर और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी होंगे। रोड शो के लिए, पुलिस ने एक यातायात सलाह जारी की है, और कार्यक्रम समाप्त होने तक कई क्षेत्र आम जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। झझप्रधानमंत्री राजभवन में रात

पीएम मोदी के 400 पार का सपना

दक्षिण भारत की 131 सीटों में से बीजेपी अगर 60 से 70 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है तभी जाकर पीएम मोदी के 400 पार का सपना साकार हो सकता है। कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन करके राज्य की 29 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयारी कर रखी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी ने एक बार फिर टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। आंध्र प्रदेश में खाता खोलने की चुनौती है। तेलंगाना में बीजेपी को अपनी 4 सीटों को बढ़ाकर 6 से 8 करनी होगी। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी लगातार मशक्कत कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एक्टर थलापति विजय ने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। जिसका नाम तमिझगा वेत्री कड़गम रखा है।

पर्यावरण को सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी: चौधरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के लिये आज 'छत्तीसगढ़ विजन 2047' पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत ने की।

पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोडमेप पर चर्चा करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को बदलते हुए वक्त को समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खुद को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार सतत विकास के लिए अपने बजट में 2047 में छत्तीसगढ़ को भी विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में देखना चाहती है और इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल के रूप में ही अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट ञ्च 2047 की तैयारी की जा रही है जिसे छत्तीसगढ़ की स्थापना के दिन 1 नवंबर को लांच किया जाएगा।

मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास का होना अनिवार्य है और इस सेक्टर में काफी ग्रोथ भी हो रही है। इसके साथ ही हमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाने की आवश्यकता है और अगले पांच साल में इसे बढ़ाने के लिए काम करना है। इसकी शुरुआत भी कर दी गयी है और अगले तीन साल के भीतर नवा रायपुर इनोवेशन तथा आईटी हब के रूप के जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू होगी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें ये जानकारी हैरानी होगी कि बड़े शहरों में उद्योगों से ज्यादा प्रदूषण सड़क पर चल रही वाहनों के जरिए होता है और इस पर नियंत्रण पाना बेहद जरुरी है। इसके लिए हम सभी को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है और ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को संरक्षण करने में अपनी महती भूमिका निभाए। छत्तीसगढ़ - विजन 2047 पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव तथा छत्तीसगढ़ सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि हमने अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो साल 2047 तक भविष्य कैसा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे प्रत्येक जीवित इंसान की सेहत उसके लिए जरूरी है वैसे ही पेड़ पौधों की अच्छी सेहत हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, उनके भीतर भी जीवन है और उनके जीवन से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। श्री भगत ने कहा कि आज तकनीक का दौर है और इसमें तेजी से बदलाव आ रहा है, लेकिन हमें इस बदलाव में भी पर्यावरण का ध्यान रखना होगा ताकि हम खुद और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ - विजन 2047 पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की अध्यक्ष श्रीमती आर शंगीता, सदस्य सचिव श्री पी. अरूण प्रसाद तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री अयाज तंबोली, प्रदेश के इंटीग्रेटेड स्टील एवं स्पंज आयरन प्लांट, कोल वॉशरी, ताप विद्युत संयंत्र, कोल माईंस, आयरन ओर माईंस, बड़े हॉस्पिटल, स्पंज आयरन एसोसिएशन के प्रतिनिधि, रोलिंग मिल मिनी स्टील प्लांट तथा माईनर मिनरल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं भिलाई नगर पालिक निगम के आयुक्तगण भी उपस्थित रहे।

प्रमुख समाचार

चुनावी बॉण्डः दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेटः राहुल

ठाणे। राहुल गांधी ने ठाणे में एक रैली में कहा कि राजनीतिक दलों को तोड़ने और विपक्षी दलों की सरकारों को

गिराने के लिए धन चुनावी बॉण्ड से आया। चुनावी बॉण्ड दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट था। राहुल गांधी ने कहाकहा कि सीबीआई-ईडी जैसी चीज नहीं है। वो अब बीजेपी के औज़ार हैं, वो उनके कंट्रोल में हैं। चोहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई-ईडी हो , यह अब भाजपा और आरएसएस के हथियार हैं...उनको यह भी सोचना चाहिए कि किसी ना किसी दिन भाजपा की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी देता हूं कि यह फिर से कभी नहीं होगा। राहुल ने कहा कि किसी भी विपक्षी दल की राष्ट्रीय स्तर पर अनुबंधों तक पहुंच नहीं है। कोई भी विपक्षी दल सीबीआई, आईटी या जबरन वसूली निदेशालय को नियंत्रित नहीं करता है। इन सभी को सीधे तौर पर भाजपा और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

कोयंबटूर में मोदी के रोड शो को नहीं मिली इजाजत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को शहर की अपनी यात्रा के दौरान कोयंबटूर में एक रोड शो की योजना बनाई है। भाजपा ने शहर पुलिस से संपर्क कर मेट्टुपालयम रोड पर एरू कंपनी से आरएस पुरम तक चार किलोमीटर लंबे रोड शो की अनुमति मांगी। हालांकि अब खबर आ रही है कि पीएम मोदी के कोयंबटूर रोड शो को मंजूरी नहीं दी गई। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के अधिकारी कोयंबटूर पहुंचे, शहर के पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की और मार्ग का सर्वेक्षण किया। भाजपा के कोयंबटूर जिला अध्यक्ष रमेश कुमार की तरफ से रोड शो में एक लाख से अधिक लोग भाग लेने की बात कही जा रही थी और प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि रोड शो के अंत में मोदी आर एस पुरम में प्रधान डाकघर के पास जनता को संबोधित करने की योजना बनाई। यह वही जगह है जहां 14 फरवरी 1998 को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को बोलने का कार्यक्रम था, जब शहर में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे। बैठक से बमुश्किल एक घंटे पहले आडवाणी ने अपनी बैठक रद्द कर दी।

एक देश एक चुनाव की शुरुआत जम्मू-कश्मीर से करनी चाहिए: अब्दुल्ला

जम्मू। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कल होने वाले आम चुनाव की तारीखों की घोषणा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईसीआई से कोई उम्मीद नहीं है। ईसीआई का काम लोकतंत्र कायम करने का है, उन्हें लोकतंत्र कायम करने में रोल अदा करना चाहिए। जम्मू-कश्मीर को चुनाव देखे हुए करीब 10 साल हो गए है। रामनाथ कोविंद ने एक राष्ट्र, एक चुनाव पर रिपोर्ट पेश की है। अगर इसकी शुरुआत जम्मू-कश्मीर से नहीं कर सकते तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है ये लोगों को धोखा देने के लिए तो नहीं है। यहां लोकतंत्र कायम करने का ये सुनहरा मौका है। भारतीय चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। ईसीआई ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की भी घोषणा करेगा। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार आम चुनाव 2024 और कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल, 16 मार्च को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी।

प्रदेश के चार शहरों में चलेंगी 240 ई-सिटी बसें, मिली स्वीकृति

रायपुर। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरो की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है जिसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40 इस प्रकार कुल 240 ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों-रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, और कोरबा को पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा, हमारे राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी। यह पहल हमें पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों का इस चैलेंज में सफल होने पर बधाई दी एवं भविष्य मे और शहरों के इस योजना मे सम्मिलत करने हेतु प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव ने कहा, डबल इंजन की सरकार के कारण हम नवाचार और स्थिरता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।

चिंता का विषय बनी हुई है म्यांमार की स्थिति- विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। म्यांमार के रखाइन राज्य में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने सभी भारतीयों को वहां से हटने और चले जाने को कहा है। हमने रखाइन राज्य के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, वहां हालात बेहद नाजुक हैं, सुरक्षा स्थिति खराब हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने शुक्रवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमने सभी भारतीय नागरिकों से जगह को खाली करने और वहां से चले जाने के लिए कहा है और हमने अपने नागरिकों से भी कहा है जो वहां हैं या कहीं और से हैं, वे उस हिस्से की यात्रा न करें। सुरक्षा स्थिति में गिरावट के कारण म्यांमार में स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वहां काफी लड़ाई हो रही है, जिससे यह रेखांकित होता है कि रखाइन राज्य में सुरक्षा स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। यह कहते हुए कि भारत म्यांमार में शांति और स्थिरता चाहता है। जायसवाल ने कहा कि वहां बहुत लड़ाई हो रही है, और सुरक्षा स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन हम सभी पक्षों से आह्वान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम देश में शांति और स्थिरता चाहते हैं, हम देश में रचनात्मक बातचीत चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि बातचीत और रचनात्मक जुड़ाव के माध्यम से समावेशी संघीय लोकतंत्र स्थापित हो।

मोदी ने कांग्रेस की साजिश की नाकाम

अजय सेतिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या ये कहिए कि मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अडंगा डालने की कांग्रेस की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रोकने के लिए कांग्रेस ने 11 मार्च को सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मोदी सरकार ने दिसंबर 2023 में संसद के शीत शिविर में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए जो क़ानून बनाया था, कांग्रेस ने उस क़ानून को चुनौती दी थी। पहले एक एनजीओ एडीआर जनवरी में सुप्रीमकोर्ट गया, उसने क़ानून पट स्टे लगाने और तुरंत सुनवाई शुरू करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। फिर फरवरी में एडीआर ने दुबारा कोशिश की, तो कोर्ट ने फिर स्टे देने और तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन 11 मार्च को जब कांग्रेस की एक नेता ने याचिका दाखिल की, तो 13 मार्च को सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर याचिका 15 मार्च को सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई। हैरानी यह जानकर हुई कि चीफ जस्टिस ने जल्दबाजी में कांग्रेस की याचिका क्यों स्वीकार की, जबकि दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार ने 14 मार्च को ही मीटिंग बुलाई हुई थी। राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस की नेता ने यह याचिका इसलिए दाखिल की थी, ताकि मोदी सरकार नए चुनाव आयुक्त नियुक्त न कर सकें।

सुप्रीमकोर्ट शायद मीडिया की खबरों से गलतफहमी में रहा कि मीटिंग 15 मार्च को है। अब ऐसा संभव नहीं लगता कि सुप्रीमकोर्ट नियुक्ति या नए चुनाव आयुक्तों के चार्ज ग्रहण करने में कोई अडंगा डालने की कोशिश करेगी। मोदी सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर ही संसद से क़ानून बनवा कर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय की है, उसी प्रक्रिया के तहत ही नियुक्ति हुई है। सरकार ने एक सिलेक्ट कमेटी बनाई है, जो एक पैनल तैयार करती है, उसी के अंतर्गत पहले 212 अधिकारियों का पैनल बना। फिर उसमें से छंटाई करके छह लोगों का पैनल बना, जिसमें संजय मिश्रा, पीसी मोदी, जेपी महापात्रा, दिनकर गुप्ता, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम थे।

उम्मीद के मुताबिक़ ही कमेटी के कांग्रेसी सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए, लेकिन कमेटी में सरकार का बहुमत होने के कारण सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम तय हो गए। जिस क़ानून के अंतर्गत दोनों अधिकारियों का चुनाव आयुक्त के तौर पर चयन हुआ है उस क़ानून पर खुद सुप्रीमकोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का एतराज उसी क़ानून पर था, जिसे संसद ने पास किया है। पिछले 75 सालों में कांग्रेस और गैर कांग्रेस सरकारों ने भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कोई क़ानून नहीं बनाया था। सरकार की मशीनरी एक पैनल बना देती थी, जिसे प्रधानमंत्री के सामने रखा जाता था, प्रधानमंत्री सबका रिकार्ड देख कर, अपने विधि मंत्री से सलाह करके उनमें से एक का नाम नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को भेज देते थे।

1992 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, उस समय के चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से टकराव शुरू किया तो राव सरकार ने क़ानून बना कर चुनाव आयुक्तों की संख्या एक से बढ़ा कर तीन कर दी, और तीनों के अधिकार भी बराबर कर दिए, लेकिन उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया वही की वही रही। जवाहर लाल नेहरू के काल से चली आ रही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ, सरकार ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती थी। पचहतर साल से एक ही परंपरा चलती रही, लेकिन जैसे ही केंद्र में स्पष्ट बहुमत वाली पहली गैर कांग्रेस सरकार आई, कई एनजीओ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोर्ट चले गए। उन्हें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में खोट दिखाई देने लगा। कांग्रेस ने जब नवीन चावला और एमएस गिल को पहले चुनाव आयुक्त बनाया और बाद में वे मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तब तक इन एनजीओ को कोई एतराज नहीं था। एमएस गिल के रिटायर होते ही जब सोनिया गांधी ने उन्हें राज्यसभा में लाकर केंद्र में मंत्री बना दिया था, तब भी इन एनजीओ को कोई चुनाव आयुक्त पक्षपाती नहीं लगा। जबकि अहमदाबाद के दस आईआईएम प्रोफेसरों के एनजीओ एडीआर ने मोदी सरकार बनने के छह महीने बाद पहली जनवरी 2015 को ही सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बदलने की याचिका दाखिल कर दी। याचिका में कहा गया था कि जैसे जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम बना हुआ है, वैसे ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम बने, जिसमें सरकार का कोई दखल नहीं हो। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एडीआर ने तुरंत सुनवाई की दरख्वास्त लगाई तो 23 अक्टूबर 2018 को सुनवाई के बाद दो जजों की बेंच ने यह केस पांच जजों की बेंच को रेफर कर दिया था।

लगातार बिजली गुल से परेशान ग्रामीण हुए लामबंद

■ जमकर किया हंगामा, तय हुआ कटौती का समय

गरियाबंद। जिले के छुरा में लगातार हो रहे बिजली कटौती के विरोध में आज ग्रामीण लामबंद हो गए। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मियों की ओर से रात के अंधेरे में चुपके से फेस का जंफर काटने से सिंचाई पंप बंद होने के कारण फसल बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही परीक्षा दे रहे छात्र भी पढ़ाई नहीं कर पाने से परेशान है। ग्रामीणों के हंगामे के बाद बिजली कटौती का समय तय किया गया है।

दरअसल, जिले के छुरा वितरण केन्द्र में रवि फसल के लिए ज्यादातर किसान विद्युत पंप पर आश्रित हैं। ऐसे में ज्यादा लोड होने के कारण बिजली विभाग लोड सेडिंग बताकर अघोषित कटौती शुरू कर दिया था। ग्रामीणों के सो जाने के बाद फेस काटने कर्मियों को आधी रात को भेजा जाता था।

कानसिंघी फीडर में आने वाले विजयपुर ग्राम में गुरुवार को रात करीबन 11 बजे बिजली विभाग के वाहन में 3 कर्मी बिजली काटने पहुंचे थे। फेस डाउन

करते ही जब बिजली गुल हुई तो रात को खलिहान इलाके में घूम रहे युवकों की नजर कर्मियों पर पड़ी। कर्मी बिजली काटकर जाते उससे पहले 10 से15 ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। आसपास के गांव से लोग पहुंचना शुरू किए तो सरकारी वाहन छोड़कर कर्मी भाग खड़े हुए। ग्रामीणों की भिड़ ने विभाग के अफसरों को कॉल किया। इस पर रात में ही एई उमेद दीवान मौके पर पहुंचे और किसी तरह ग्रामीणों को शांत कराया।

निर्धारण हुआ बिजली कटौती का समय

रात की घटना शुक्रवार सुबह होते ही प्रभावित गांवों में आग की तरह फैल गई। विजयपुर के अलावा देवरी, पेंड्रा, सिवनी समेत 8 गांव के 100 किसान सिवनी कृषि मंडी के पास एकत्रित हो गए। किसान मेवा नायक, जयराम, चिंता राम सिन्हा, ओंकार सिंह और अशोक ठाकुर के नेतृत्व में विभाग को घेरने को रणनीति बना रहे थे। आरोप है कि इसी इलाके में 6 से 8 घंटे की कटौती करते थे। इसके कारण फसल प्रभावित होने के साथ ही परीक्षा दे रहे छात्र परेशान थे।

इसी बीच एई उमेद दीवान दोबारा सिवनी पहुंचे और बिजली काटौती का समय निर्धारित किया गया। सिवनी सरपंच अशोक ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों ने कटौती के लिए समय निर्धारण के अलावा अवधि केवल 3 घंटा बिजली काटने पर सहमत हुए। इसके अलावा नए फीडर की मांग को भी मान लिए, जिसके बाद समझौता कर लिया गया है।

विभाग ने गिनाई मजबूरी

छुरा वितरण केन्द्र के एई उमेद दीवान ने बताया कि छुरा में 4 फीडर मौजूद है। इसमें कनसिंघी फीडर में सर्वाधिक 35 गांव होने के साथ-साथ रवि फसल सिंचाई करने वाले बोर की संख्या सर्वाधिक है। लोड ज्यादा होने की वजह से कुछ घंटे के लिए सेडिंग किया जाता है ताकि दूसरे फीडर की सप्लाई प्रभावित न हो, लेकिन इस बीच नए फीडर के काम शुरू होने या 33 केवी की सप्लाई में आए फाल्ट के वजह से हो, बिजली बंद होने से कटौती की अवधि बढ़ जा रही है। जल्द ही कनसिंघी को दो भागों में बांटा जा रहा है, जिसके बाद समस्या कम होगी। सेडिंग का टाइम शेड्यूल तय कर दिया गया है। बारी-बारी से सभी फीडर में अलग-अलग अवधी में 3-3 घंटे की कटौती की जाएगी।

तीन लड़कियों का किडनैप करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने दबोचा

बिलासपुर। जिले के सरकंडा पुलिस को तीन लड़कियों के लापता होने के केस में बड़ी सफलता मिली है। तीनों लड़कियों का एक आरोपी ने अपहरण किया और उन्हें अपने घर में कैद कर रखा था। लापता होने की शिकायत मिलने पर पुलिस की जांच पड़ताल में इसका खुलासा हुआ। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर छापा मारकर तीनों लड़कियों को बरामद किया और उनके परिजनों को सौंप दिया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस केस की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र की निवासी दो नाबालिक और एक बालिग लड़की 11 मार्च को अचानक लापता हो गई थी। परिजनों के शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया और लड़कियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने साइबर टीम की भी मदद ली और जिस मोबाइल नंबर से लड़कियों की बात हो रही थी, उसे ट्रेस किया। मोबाइल का लोकेशन मिलते ही फौरन पुलिस ने तोरवा थाना क्षेत्र के बापू नगर इलाके के अक घर में छापेमार कार्रवाई की। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम बनाई गई और उसके घर की घेराबंदी कर छापा मारा गया। पुलिस को घर के एक कमरे में आरोपी मिला। वह पुलिस को देखते ही भागने लगा, जिसे पकड़ लिया गया। घर की तलाशी लेने पर एक कमरे में तीनों लड़कियां

बंद मिली, जिन्हें कमरे से बाहर निकाल कर पुलिस थाना लाया गया। जहां लड़कियों से पूछताछ के बाद उन्हें परिजन को सौंपा गया है। वहीं आरोपी विनय मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

टीआई, रौशन आहूजा ने कहा मुख्य आरोपी विनय मलिक बिलासपुर शहर का एक आदतन अपराधी है। जिसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में अब तक लगभग 2 दर्जन मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने छापा मारकर आरोपी विनय को उसके घर से गिरफ्तार किया है। दरअसल, बिलासपुर पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। इस केस में लड़कियों के अपहरण में कई आरोपियों के शामिल होने की आशंका पुलिस जता रही है। आरोपी तक लड़कियां कैसे पहुंची, लड़कियों का आरोपी क्या करने वाले थे और इसमें कौन-कौन शामिल है, इस दिशा में सरकंडा थाना पुलिस जांच कर रही है।

कोरिया में कोरबा लोकसभा प्रत्याशी

सरोज पांडे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ छत्तीसगढ़ी गीत पर थिरकी

कोरिया। कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे इस समय जोरदार चुनाव प्रचार कर रही है। सरोज पांडे आए दिन अपने लोकसभा सीट की अलग अलग विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रही है। गुरुवार को पांडे कोरिया पहुंची।

गुरुवार को कोरिया में भाजपा की तरफ से मंडलवार कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे भी पहुंची। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सरोज पांडे का जमकर स्वागत किया। उनके स्वागत में सरगुजिहा गीत गाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जमकर नृत्य किया। उनके उत्साह को देखते हुए सरोज पांडे भी खुद को ना रोक सकी और उनके बीच पहुंचकर थिरकने लगी। सरोज पांडे को अपने बीच पहुंचकर महिलाएं और ज्यादा उत्साहित हो गई खूब नृत्य किया।

इस दौरान सरोज पांडे ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं की काफी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी योजनाओं को जनता के आखिरी छोर

तक पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हीं के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है।

कोरबा लोकसभा सीट में आठ विधानसभा पड़ते हैं। यह सामान्य वर्ग की सीट है। कोरबा, कटघोरा, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, मरवाही, रामपुर, पाली तानाखार, भरतपुर सोनहत विधानसभा इस लोकसभा में पड़ते हैं। रामपुर, पाली तानाखार, भरतपुर सोनहत आरक्षित विधानसभा सीटें हैं। इस वजह से कोरबा लोकसभा के सीट में शहरी के साथ ही आदिवासी मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है।

नौकरी लगाने का झांसा देकर मामी ने भांजे से की 50 लाख की धोखाधड़ी

दुर्ग भिलाई। जिले के भिलाई 3 थाना क्षेत्र में खाद्य निरीक्षक की नौकरी लगवाने का झांसा देकर धोखाधड़ी की शिकायत मिली है। पीड़ित से धोखाधड़ी करने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी मामी ही है। आरोपी मामी ने अपने ही भांजे को नौकरी का झांसा देकर 50 लाख रुपये की ठगी की है। इसमें महिला के साथ दो और आरोपी भी शामिल हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

भिलाई 3 थाना के टीआई अंबर सिंह ने बताया, साल 2022 में पीड़ित गजेंद्र लहरे की मामी सुनीता सोनवानी ने उसकी आरोपियों से मुलाकात कराई थी। इस दौरान दूसरे आरोपी नरेंद्र देशलहरे ने मंत्रालय में अपनी पहुंच बताकर गजेंद्र की खाद्य निरीक्षक पद पर नौकरी लगवाने की बात कही। जिसके लिए उसने 50 लाख रुपये में बात पक्का कर लिया। जिसके बाद पीड़ित ने 17 फरवरी 2022 को 25 लाख रुपये और फिर 01 अगस्त 2022 को 25 लाख रुपये आरोपियों को दिया।

टीआई अंबर सिंह ने कहा नौकरी की आस में भांजे ने अपनी मामी को 50 लाख रुपये दिए थे। लेकिन जब पीड़ित गजेंद्र की नौकरी नहीं लगी तो उसने आरोपियों से रुपये लौटाने के लिए कहा। जिस पर आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और उल्टे जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है।

पीड़ित गजेंद्र लहरे ने अपनी जमीन और घर बेचकर सरकारी नौकरी के लिए अपनी मामी को 50 लाख रुपये दिए थे। पहले किश्त के लिए उसने अपने पिता के साथ मिलकर 25 लाख रुपये में जमीन बेची। इसके बाद पीड़ित ने अपना घर बेचकर दूसरी किश्त 25 लाख रुपये दिए। कुल 50 लाख रुपये देने के बाद भी पीड़ित की नौकरी नहीं लगी और आरोपियों ने भी पैसे नहीं लौटाए। जिसके बाद पीड़ित गजेंद्र ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

चरोदा निवासी गजेंद्र लहरे की शिकायत पर उसकी मामी सुनीता सोनवानी, सहायक ग्रेड तीन कर्मचारी नरेंद्र देशहलरे और उसकी पत्नी निवेदिता देशलहरे के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत केस दर्ज किया है। भिलाई 3 थाना पुलिस केस की जांच कर रही है।

जुआरी निकले भाजपा नेता प्रवेश शर्मा और नागेश साहू

जंगल में सजी थी जुए की महफिल, 10 गिरफ्तार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को पकड़ा है। इन आरोपियों में भाजपा नेता भी शामिल हैं। जिन्हें पुलिस ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के पास नगदी रकम और मोबाइल फोन समेत ताश पत्ती बरामद की है।

दुर्ग एसपी जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगाता जारी है। इसी कड़ी में प्रशिक्षु डीएसपी अजय ठाकुर और नंदिनी थाना प्रभारी राजेश साहू के नेतृत्व में जुए के दो अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। जिसमें मुरमुंदा चेटुवा रोड के तालाब के पास जुआ खिलाते पांच जुआरियों को गिरफ्तार किया है।

वहीं, दूसरी कार्रवाई में मुरमुंदा के नहर किनारे जुआ खेल रहे पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान मिथलेश साहू, आशुतोष तिवारी, राजकुमार ठाकुर, प्रवेश शर्मा, नागेश साहू, दीपक गायकवाड़, भुनेश्वर जोशी, महेन्द्र जोशी, रोशन टंडन और खिलेन्द्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से 19 हजार नगद, मोबाइल समेत ताश पत्ती बरामद की है। सभी के खिलाफ जुआ के एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने जुआ खेलने वाले जिन 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें भाजपा नेता भी शामिल हैं। जिसमें अहिवारा मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रवेश शर्मा और भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री नागेश साहू को जुआ खिलाने के लिए पुलिस ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। नंदिनी थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ताश पत्ती के माध्यम से पैसे का हार जीत खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर दो स्थानों पर कार्रवाई को गई है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कवर्धा में 12वीं की एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम सेंटर बना

कवर्धा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश भर में 12 वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू हुई है। हजारों लाखों छात्र छात्राएं एग्जाम दे रहे हैं। इन सब के बीच हम आपको एक ऐसे परीक्षार्थी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए बेहद खास है। दरअसल इस एक अकेली परीक्षार्थी के लिए एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। खास बात यह भी है कि इस एक छात्रा की एग्जाम के लिए काफी मशक्त की गई है। परीक्षा केंद्र प्रभारी, सहायक केंद्र प्रभारी, चपरासी, सुरक्षाकर्मी समेत 7 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक मुख्यालय में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में यह परीक्षा केंद्र है। इसमें 12 वीं साइंस की एक छात्रा एग्जाम दे रही है। इस छात्रा के लिए शिक्षा विभाग ने नियमित कर्मचारी और स्टाफ कि ड्यूटी लगाई गई है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जेपी बनर्जी ने कहा पंडरिया ब्लॉक में सरस्वती शिशु मंदिर में एक छात्रा के लिए सेंटर बनाया गया है। छात्रा एमबीशन प्राइवेट स्कूल की स्टूडेंट है। अच्छे से परीक्षा हो रही है।

रामलला दर्शन योजना पर फैसला सुरक्षित

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी श्री रामलला दर्शन योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई पूरी करते हुए इस पर उच्च न्यायालय ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। देवरी खुर्द निवासी सामाजिक कार्यकर्ता लखन सुबोध की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। रामलला दर्शन की योजना संविधान में निहित शर्तों के विपरीत है। उन्होंने इस योजना को बंद करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश देने की मांग की। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह योजना किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं है। यह प्रदेशवासियों के भ्रमण की योजना है। जो गरीब लोग आर्थिक व्यवस्था नहीं होने के कारण धार्मिक यात्रा पर नहीं जा पाते उन्हें अयोध्या ले जाया जा रहा है। जहां वे श्री राम लला का दर्शन कर वापस लौटेंगे। इसका किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति लाभ ले सकता है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण में लेटलतीफी

बिलासपुर। न्यायधानी के पुराना बस स्टैंड में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण कार्य चल रहा है। जिसमें लेटलतीफी को लेकर ठेका कंपनी पर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। निगम प्रशासन ने यह जुर्माना कोलकाता की ठेका कंपनी सिम पार्क पर लगाया है। स्मार्ट सिटी के तहत छत्तीसगढ़ की पहली आटोमेटेड मल्टीलेवल शटल टाइप कार पार्किंग का निर्माण बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड परिसर में कराया जा रहा है, जो पूरी तरह से स्वचालित आटोमेटेड शटल टाइप कार पार्किंग होगी। जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर ले जाकर कार खड़े करते ही आटोमेटिक सिस्टम से कार ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाएगी। करीब साढ़े दस हजार स्क्वेयर फीट एरिया में शटल टाइप मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाई जा रही है। यह चार मंजिला कार पार्किंग होगी। पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर में बाइक पार्क किया जाएगा और इसमें 80 कारों को पार्क करने की व्यवस्था रहेगी। स्मार्ट सिटी से कुल 12 करोड़ 60 लाख राशि की लागत से इस आटोमेटिक कार पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है।

खाद्य मंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

बेमेतरा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड के नगर पंचायत मारो में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 1 करोड़ 78 लाख 14 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया । विकास कार्यों के भूमि पूजन में विभिन्न वार्डो में आर सी सी नाली, सी सी रोड, एवं मंगल भवन शामिल है। खाद्य मंत्री ने हितग्राहियों नये राशन कार्ड का भी वितरण किया। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत 24.72 लाख किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रूपए की अदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नया रिकार्ड प्रदेश में बना है। 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।

सुरक्षा में कोबरा ने की सेंध लगाने की कोशिश

कोरबा। कोरबा के आईटी कॉलेज स्थित विधानसभा निर्वाचन रूम की सुरक्षा में एक कोबरा ने सेंध लगाने का प्रयास किया। वहां तैनात जवानों की नजरों से बचकर विशालकाय कोबरा अंदर घुसपैठ करने की फिराक में था, लेकिन एक जवान ने उसे देख लिया। कोबरा को इतने करीब देखकर जवानों में अफरातफरी मच गई। सुरक्षाकर्मियों ने सांप को मारने के बजाए उसके रेस्क्यू के लिए वाइल्डलाइफ रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष को सूचना दी जिसके बाद जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंचे और कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली। कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। जितेंद्र सारथी ने बताया अब सांप गर्मी और धूप से बचने के लिए लगातार ठंडे की तलाश में घरों में घुसने का प्रयास करेंगे, साथ ही उनके प्रजनन का भी समय है। स्नेक कैचर जितेंद्र सारथी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे के आसपास आईटी कॉलेज स्ट्रांग रूम में तैनात सुरक्षा पहले के द्वारा फोन कर जानकारी दी गई की एक कोबरा सांप फन फैलाए बैठा हुआ है।

जनपद सीईओ को हटाने की मांग, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप

■ कलेक्टर बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई

गरियाबंद। जिला मुख्यालय के जनपद पंचायत में पदस्थ सीईओ के रैवेये से नाराज जनपद अध्यक्ष, उपाधक्ष समेत 13 सदस्यों ने सीईओ को हटाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप में शिव सेना ने भी सीईओ का पुतला फूंका। शिकायत पर कलेक्टर ने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई करेंगे।

गरियाबंद जनपद पंचायत सीईओ पद्मनी हरदेल के खिलाफ आज जनपद अध्यक्ष डालिमा ठाकुर, उपाधयक्ष प्रवीन यादव समेत 13 सदस्य कलेक्टोरेट पहुंचे और उसे हटाने का ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के समक्ष सौंपे गए ज्ञापन में जनपद प्रतिनिधियों ने महिला अफसर पर कई संगीन आरोप लगाए हैं।

ज्ञापन में बताया गया है कि हरदेल जिला पंचायत में सहायक संचालक के पद में हैं, उन्हें 4 माह पहले जनपद का अतरिक्त प्रभार दिया गया है। पावर वाले पद के कारण कोई इन्हें रोकने टोकने वाले नहीं है। ऐसे में वे ज्यादातर समय जनपद से गायब रहती हैं। अब तक केवल एक बार समान्य सभा की बैठक हुई। इसमे भी पारित बिंदुओं पर कोई अमल नहीं किया गया। कॉल करने पर वो रिसीव नहीं करते। कक्ष में बैठने के दरम्यान चुने गए आदिवासी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यहार करते हैं।

ज्ञापन में आगे कहा गया है कि जिला पंचायत के अफसरों का सपोर्ट रहता है, जिसके चलते हमेशा तानाशाह रवैया अपनाते हैं। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि बगैर अनुमोदन के सीईओ ने विवेकानंद प्रोत्साहन की राशि छत्तीसगढ़िया खेल में खर्च किया है। जनपद बॉडी के इस ज्ञापन को कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इधर जब जनपद सदस्य कलेक्टोरेट में ज्ञापन दे रहे थे तो दूसरी ओर नगर के मुख्य चौराहे में शिवसेना ने सीईओ का पुतला फूंक दिया। शिवसेना का आरोप है कि भ्रष्टाचार करने वाले कई पंचायतों की शिकायत जनपद में की गई है। किसी पर भी न जांच बैठी न कार्यवाही हुई है। इससे आक्रोशित शिव सैनिकों ने सीईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उनका पुतला जलाया।

जनपद सीईओ ने सभी आरोप को बताया झूठ

इस मामले में जनपद सीईओ पद्मिनी हरदेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दो जगह की जिम्मेदारी के कारण दोनों जगह काम संभाल रही हूं। रही बात बैठक की तो आचार संहिता की बची अवधी में दो बार होना था, दो बार बैठक की गई। दुर्व्यवहार के आरोप पर कहा कि मैं एक महिला हूं, जनप्रतिनिधि भी ज्यादातर महिला हैं, दुर्व्यवहार का सवाल ही नहीं उठता।

पूर्व मंत्री के करीबी समेत 4 भाजपा में शामिल

कवर्धा। कबीरधाम में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार लोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष अनारा साहू, अध्यक्ष प्रतिनिधि मुखी साहू, पूर्व अध्यक्ष व पार्षद उषा सेन, पूर्व पार्षद मनहरण सेन ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक साहू ने चारों नये सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई।

लोहारा नगरपंचायत को पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का गढ़ माना जाता है। मोहम्मद अकबर ने ही लोहारा नगरपंचायत में अपने नजदीकी मुखी साहू की पत्नी अनारा साहू को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद नजदीकी लोग अब दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद जिले में नगरपालिका व नगरपंचायत में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही कांग्रेस के कब्जे से अध्यक्ष की कुर्सियां धीरे-धीरे खिसकते जा रही है।

पहले पांडातराई नगरपंचायत कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी अविश्वास प्रस्ताव से गिरा दी गई और भाजपा का कब्जा हो गया, फिर कवर्धा नगरपालिका के कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफा के बाद कांग्रेस की पूर्ण बहुमत होने के बाद भी शासन ने नगरपालिका अधिनियम 1961 के तहत धारा 37/2 का उपयोग करते हुए भाजपा पार्षद मनहरण कौशिक को अध्यक्ष बनाया। हालांकि कांग्रेस पार्षदों ने इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब लोहारा नगरपंचायत अध्यक्ष अनारा साहू अपने पार्षद व पूर्व अध्यक्ष व पूर्व पार्षद के साथ भाजपा में शामिल हो गई है।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस के बचे सीटों में चार पर नाम तय,बस्तर में पेंच फंसा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की 11 सीटों के लिए कांग्रेस ने 6 सीटों पर पहले ही नाम की घोषणा कर दी है। बचे पांच सीटों पर दिल्ली में चली मैराथन बैठक के बाद चार सीटों के लिए भी लगभग सिंगल नाम तय हो चुके हैं केवल घोषणा बाकी है इनमें बिलासपुर से विष्णु यादव,सरगुजा से शशि सिंह,रायगढ से डा.मेनका व कांकेर से विरेश ठाकुर का नाम शामिल हैं। एक मात्र सीट बस्तर ने उलझा रखा है जहां लखमा के बेटे या स्वंय लखमा व पीसीसी प्रमुख दीपक बैज के बीच रस्साकशी चल रही है। ये भी बताया जा रहा कि बैज अब चुनाव नहीं लडने की इच्छा रख रहे हैं,हालांकि वे यह भी कह रहे हैं कि पार्टी का हर निर्णय मंजूर है। माना जा रहा है कि सभी पांच नाम 18 मार्च को घोषित हो सकते हैं।

कमल सोनी स्वच्छ भारत के सर्वेक्षण 2024 के बिलासपुर एंबेसडर बने

बिलासपुर। भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत के सर्वेक्षण 2024 टूल किट में सिटीजन एंगेजमेंट के तहत स्मपूर्ण भारत वर्ष में नगरी निकाय में ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किए गए हैं जिसमे बिलासपुर नगरी निकाय में से 20 लोगो जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हे ब्रांड एंबेसडर बनाया गया हैं जिसमे उपमुख्यमंत्री अरुण साव से लेकर कमल सोनी समाज सेवी के साथ सराफा एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष को भी बनाया गया हैं इनके अलावा डा कमल किशोर, डा विनोद तिवारी,मुकुल तिवारी,डा ए के वर्मा,रोशन तिवारी,एविन खान,निधि तिवारी,उमा नेताम,प्रकाश,नवदीप सिंग,मोनिका लांबा,किरण चावला,नितिन,विपुल शर्मा,कुलदीप पुनिया, शांतनु खंडेलवाल,निशु सिंह,विशाल पाठक भी बनाए गए।

घर में घुसकर परिवार के लोगों को बंधक बनाकर पीटा, फिर लाखों रुपए लुटे लुटेरे

रायपुर। रायपुर के माना थाना क्षेत्र में लाखों रुपये की लूट का मामला सामने आया है। चार लुटेरों ने मिलकर एक परिवारों को बंधक बनाकर लुट की घटना को अंजाम दिया है। लुटेरे पहले घर घुसे, लेकिन उनकी आहाट सुनकर परिवार के लोग उठ गए। इसके बाद चोरों ने परिवार के लोगों को डराया धमकाया, इतना ही नहीं बंधक बनाकर पिटाई भी कर दी। फिर मास्टर चाबी से अलमारी का ताला खोलकर नगदी रकम लगभग 10 लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। मामले की जानकारी के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार की है। लगभग रात तीन बजे चेहरे में नकाब पहनकर चार लुटेरे घर में घुस गए। इसके बाद उनकी आवाज सुनकर घर में मौजूद लोग उठ गए। इस दौरान चोरों डराया धमकाया और बंधक बनाकर पिटाई कर दी। इसके बाद घर अंदर रखे अलमारी को मास्टर चाबी से खोलकर लगभग 10 लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। इसके बाद घर में मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर घटना स्थल पहुंची। और मामले की जांच में जुट गई है।

दो दिवसीय डाक जीवन बीमा जागरूकता शिविर संपन्न

रायपुर। भारतीय डाक विभाग रायपुर संभाग की टीम के द्वारा प्रवर अधीक्षक डाकघर रायपुर के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य संचालनालय परिसर नया रायपुर में दो दिवसीय डाक जीवन बीमा जागरूकता शिविर 13 एव14 मार्च को आयोजित किया गया। इस शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को डाक जीवन बीमा सहित डाकघर की अल्प बचत योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इन दो दिनों में लगभग 150 से भी ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शिविर स्थल पहुंचकर डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित पूछताछ कर जानकारी लिए। इस दौरान 50 लाख बीमा राशि की डाक जीवन बीमा और एमआईएस, सीनियर सिटीजन अकांउट सहित बचत खाते खोलने हेतू फॉर्म उपलब्ध कराई गई थी। इस शिविर के आयोजन के लिए संचालक स्वास्थ्य सेवाएं और उपसंचालक डा महेंद्र सिंह का विशेष सहयोग मिला।

बृजमोहन ने निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण

रायपुर दक्षिण में विकास कार्यों के लिए 1.90 करोड़ देने की घोषणा

रायपुर। शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केन्द्र और राज्य में हमारी डबल इंजन सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य में विकास की गति तेज हो गई है। आने वाले समय में यहां विकास कार्य और तेज़ी से होंगे। मंत्री श्री अग्रवाल रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हुए करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में विकास का काम ठप हो गया था। राजधानी रायपुर में विकास के बजाए विनाश के काम होते थे। लोग खस्ताहाल सड़कों से परेशान थे। लेकिन हमारी सरकार आते ही अल्प अवधि 3 महीने में ही विकास कार्यों में तेजी आई है, सालों से अटके कार्य पूरे हो रहे हैं।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि, बीते 40 वर्षों से मुझे रायपुर की जनता से जो प्रेम और आशीर्वाद मिला है, जिसके कारण मैं विधायक और मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव के लिए काम कर रही है। जन-धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ

भारत अभियान, के साथ ही अस्पताल, स्कूल, सड़कों, आधो संरचना विकास, कृषि और पर्यटन उद्योग में भी सुधार हुआ है। हमारी सरकार ने विकास के लिए नई योजनाएं लागू की हैं और लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार पूरे भी किए हैं। इन सब कारणों से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने से विकास की गति तेज हो गई है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने खो-खो पारा में 100 वर्ष पुराने ऐतिहासिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 125 लाख रुपए की लागत से नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया। साथ ही स्कूल में स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही पंडित सुंदरलाल वार्ड में 5 लाख 11 हजार रुपए की लागत से वार्ड कार्यालय और खदानेश्वर महादेव मंदिर के पास 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक कक्ष का लोकार्पण किया। यहां मंदिर से मेन रोड को जोडने के लिए 10 लाख रूपए राशि सड़क निर्माण और उसके दोनो तरफ सुंदरीकरण के लिए भी स्वीकृति दी। राधा स्वामी नगर में 10 लाख रुपए और मठपारा में 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही यहां शीतला माता मंदिर के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसी प्रकार भाठागांव में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बने नगर माता बिन्नी बाई सोनकर शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया। साथ ही स्कूल में फर्नीचर, लैब, कंप्यूटर आदि के लिए 1 करोड़ रुपए और शेड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही स्कूल के पास नाले के निर्माण के लिए भी 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने स्कूल के व्याख्याता श्री बिहारी लाल शर्मा को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों से बेहतर सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने शहीद चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, भैरव नगर में 5 लाख के नव निर्मित सामुदायिक भवन और 3.5 लाख के शेड का लोकार्पण किया और शहीद पंकज विक्रम वार्ड में सामुदायिक भवन में 5 लाख की लागत से बने अतिरिक्त नव निर्मित हॉल का लोकार्पण किया। इसके अलावा टिकरापारा में 5 लाख से यादव सामाजिक भवन, चंगोराभाठा में करीब 10 लाख रुपए से बने सामुदायिक भवन और रंगमंच का लोकार्पण किया। श्री अग्रवाल ने भक्त माता कर्मा वार्ड के शिव नगर में आयुर्वेदिक अस्पताल भवन और रंगमंच को भी जनता को समर्पित किया।

इस अवसर नेता प्रतिपक्ष नगर निगम श्रीमती मीनल चौबे, उप नेता प्रतिपक्ष श्री मनोज वर्मा, पार्षद श्रीमती सरिता वर्मा, एमआईसी सदस्य श्री जितेंद्र अग्रवाल, पार्षद श्री सतनाम पनाग, श्री सुभाष तिवारी, श्री मोहन एंटी, स्थानीय नेता, नगर पालिक निगम, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

अधोसंरचना विकास और मूलभूत कार्यों के लिए 8.54 करोड़ स्वीकृत

■ **राजनांदगांव ननि वार्डों के लिए राशि स्वीकृत**

रायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम में अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों और अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कुल आठ करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना विकास के 42 कार्यों के लिए सात करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। शहर में अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत अनटाइड फंड के रुप में विभाग द्वारा एक करोड़ रुपए की भी स्वीकृति दी गई है।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा इन राशियों की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजनांदगांव में पत्रकारों के लिए आबंटित आवासीय भूखंड में द्वितीय चरण के शेष आवश्यक विकास कार्यों के लिए अधोसंरचना मद के अंतर्गत करीब दो करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें प्रेस क्लब कॉलोनी में 97 लाख 19 हजार रुपए लागत के पी.सी.सी. रोड निर्माण, 34 लाख 64 हजार रुपए लागत के आर.सी.सी. नाली निर्माण और 68 लाख आठ हजार रुपए लागत के बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य शामिल हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के लिए अधोसंरचना मद से स्वीकृत कुल सात करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए की राशि से शहर के विभिन्न वार्डों में सी.सी. रोड, पी.सी.सी. रोड, नाला एवं नाली निर्माण, सामुदायिक भवनों के निर्माण, उद्यान निर्माण, शौचालय निर्माण, गेट, दुकान एवं शेड निर्माण, डोम निर्माण, इंटरलॉकिंग, बाउंड्रीवॉल तथा अहाता निर्माण के कार्य कराए जाएंगे।

अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय

रायपुर। जमीन की खरीदी और बिक्री के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति और लोगों को सुविधाएं देने के लिए महानिरीक्षक पंजीयक ने मार्च महीने में पडने वाले 11 अवकाश के दिन होने के मद्देनजर आगामी 16 मार्च से शासकीय अवकाश शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खोलने और पंजीयन करने के आदेश जारी किए हैं।

जमीन की खरीदी और बिक्री के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति और लोगों को सुविधाएं देने के लिए महानिरीक्षक पंजीयक ने मार्च महीने में पडने वाले 11 अवकाश के दिन होने के मद्देनजर आगामी 16 मार्च से शासकीय अवकाश शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खोलने और पंजीयन करने के आदेश जारी किए हैं। यानि 16 मार्च से 31 मार्च तक कुल आधादर्जन दिनों में भी पंजीयन कार्यालय में काम होंगे।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के माध्यम से, दस्तावेजों का पंजीयन, भारतीय स्टाम्प अधिनियम एवं पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के तहत करते हुए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क के रूप में, राज्य शासन के लिए राजस्व अर्जन करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम माह पूर्ण होनें में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें से शासकीय अवकाश के 11 दिन भी शामिल है। अवकाश के दिवस में पंजीयन कार्यालय बंद रहने से दस्तावेजों का पंजीयन प्रभावित होगा, जिससे शासकीय राजस्व अर्जन का भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए जनसुविधा और शासकीय राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए मार्च महीने में शनिवार और रविवार को अवकाश के दिन भी पंजीयन कार्य होंगे।

इन 6 दिनों में खुलेंगे कार्यालय 16 मार्च शनिवार, 17 मार्च रविवार, 23 मार्च शनिवार, 29 मार्च शुक्रवार, 30 मार्च शनिवार, 31 मार्च रविवार।

हाईकोर्ट ने रद्द किया प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला आदेश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और जनपद पंचायत के सीईओ (ट्रायबल विभाग) के 215 ट्रांसफ़र आदेश को निरस्त कर दिया है। बता दें, कि राज्य सरकार ने 23 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र को आधार बनाकर ट्रांसफर किए थे, लेकिन 27 फ़रवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक अन्य पत्र जारी कर 23 फ़रवरी के पत्र में दिए गए आदेश को स्पष्ट किया, जिसके बाद इस ट्रांसफ़र आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में 60 से अधिक याचिकाएं लगाई गई थी।

दरअसल, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जनपद पंचायत के सीईओ सहित प्रशासनिक अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। राज्य शासन के इस ट्रांसफर आदेश को चुनौती देते

हुए प्रशासनिक अफसरों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ता प्रशासनिक अफसरों ने तर्क दिया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीते 27 फरवरी को लोकसभा चुनाव में कार्यकाल और ट्रांसफर को लेकर नया स्पष्टीकरण दिया है, जिसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में तीन साल के कार्यकाल का नियम केवल रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर पर लागू होता है। लेकिन, राज्य सरकार ने आयोग के निर्देशों को आधार पर बनाकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक व जनपद पंचायतों के सीईओ का भी ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रतीक शर्मा सहित अन्य वकीलों ने तर्क दिया और आयोग के स्पष्टीकरण के आधार पर तबादला आदेश निरस्त करने की मांग की। वहीं, राज्य शासन की तरफ से भी बताया गया कि चुनाव आयोग ने ट्रांसफर को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच ने तबादला आदेश निरस्त कर दिया है।

बता दें कि राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के 23 फरवरी के दिशा निर्देश को आधार बनाकर प्रशासनिक अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 49 तहसीलदार, 79 नायब तहसीलदार, 5 भू-अभिलेख अधीक्षक, 59 सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख, 23 जनपद पंचायत सीईओ का ट्रांसफर किया

स्वास्थ्य विभाग के बर्खास्त कर्मी हुए बहाल

■ **रुका हुआ वेतन मिला, 30 हजार कर्मचारियों को मिला लाभ**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बर्खास्त हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही 25 हजार कर्मियों को रुका हुआ वतन भी मिला। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर आदेश जारी हुआ है। इसका लाभ 30 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को मिला है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी 21 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक हड़ताल में थे। इस अवधि का अवकाश और रूका वेतन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर जारी कर दिया गया है। इस पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल को अभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के आंदोलन कर रहे

कर्मचारियों का उस दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्तगी और वेतन अस्वीकृत कर दिया गया था। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मुलाकात के बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को इन विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए थे। निर्देश के परिपालन में बर्खास्त पांच हजार कर्मचारियों को वापस सेवा में ले लिया गया है। साथ ही 25 हजार कर्मचारियों का अंदोलन के दौरान रूका वेतन भी स्वीकृत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का निज निवास कार्यालय में गत दिवस सौजन्य भेंट कर धन्यवाद दिया है। आंदोलन के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के दो हजार कर्मचारियों के रूके हुए वेतन को देने का आदेश जारी नहीं किया गया है। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इन कर्मियों का भी वेतन जारी करने का निवेदन स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल से किया हैं।

भाजपा ने कार्टून के जरिए कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू पर साधा निशाना

'जो भुनेश्वर साहू के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे?'

रायपुर। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 में से 11 सीटों को जीतने के लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस कड़ी में शुक्रवार को महासमुंद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर निशाना साधा है।

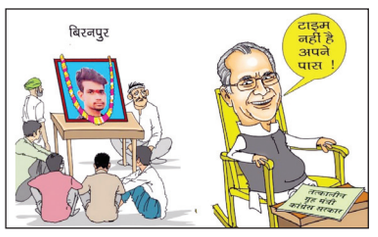

सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए अपने हैंडल से छत्तीसगढ़ भाजपा ने महासमुंद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू पर निशाना साधते हुए महासमुंदवासियों को लोकसभा क्षेत्र के रहवासियों को ताकीद किया है कि 'जो बिरनपुर में मारे गए युवक भुनेश्वर साहू के नहीं तो वो आपके क्या होंगे?'

भाजपा ने इस कार्टून के जरिए एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ 'भुनेश्वर साहू' के नाम से लोकसभा क्षेत्र में निवासरत साहू समाज को लोगों पर निशाना साधा है, तो दूसरी ओर बतौर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की लचर कार्यप्रणाली को रेखांकित करते हुए आम वोटरों को आगाह किया है। अब इस कार्टून का असर मतदान पर कितना पड़ता है, यह आने वाला समय बताएगा। भाजपा ने अपना कार्टून अभियान 11 मार्च से शुरू किया था, जब पहली बार राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 'राजनांदगांव या जिहादगांवज। चुनाव आपका है!' की बात कहते हुए निशाना बनाया गया था। इसमें भूपेश बघेल के साथ रायपुर महापौर एजाज ढेबर, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ मार्च करते नजर आ रहा है, जिसमें 'भाईजान! अलग नंबर का राजनांदगांव का है।' कह रहे हैं।

लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा एलान

नया इतिहास बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी : ओपी चौधरी

रायपुर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल चुनाव आयोग एलान करेगा। चुनाव आयोग की कवायद के साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्रियों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा को आशीर्वाद देने देश की जनता मन बना कर बैठी है। प्रधानमंत्री मोदी नया इतिहास बनाएंगे। वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि (लोकसभा चुनाव) तारीखों का ऐलान जब भी हो, हमारी पूरी तैयारी है।

मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक बहुमत के साथ तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का रिकॉर्ड कायम करेंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जरूरी है, यह जनता समझती है। वहीं प्रदेश में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के निर्माण पर कहा कि छत्तीसगढ़ की पहले सरकार है, जिसने यह विभाग बनाया है।

उन्होंने कहा कि जितनी भी विभागीय परेशानियां रहती हैं, उसे को-ऑर्डिनेट करने में और हर जगह टेक्नोलॉजी लाकर रिफॉर्म लाने और ग्रोथ को प्राथमिकता देना। यह विभाग एक मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे।

वहीं मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि तारीखों का ऐलान जब भी हो हमारी तैयारी पूरी है। सतत् संगठन का संगठनात्मक कार्यक्रम चलता रहता है। बूथ मैनेजमेंट से लेकर सारी चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता। विपक्ष के लोग समझे और देखें।

वहीं सरकार के तीन माह पूरे होने पर नेताम ने कहा कि हमारी सरकार ने गांव किसान महिलाओं नौजवानों के लिए जरूरतमंदों के लिए काम किया है। मोदी की गारंटी के तहत जो कमिटमेंट किए गए थे, उसे 3 महीने में पूरा किया। विकास के लिए हमारी सरकार ने मजबूत फाउंडेशन बनाया है। पीएससी घोटाले और युवाओं के साथ जो छलावा हुआ, उसके दोषियों को सजा भी दी जाएगी और इस पर उच्च स्तरीय जांच भी होगी।

वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मंत्री नेताम ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने की आदत है। कुछ भी आरोप लगाते हैं। 20 करोड़ से ऊपर जिनकी सदस्य संख्या हो वह पार्टी अपने आप में सक्षम है। डराने-धमकाने का काम कांग्रेस करती है। डरा-धमका कर भ्रष्टाचार के पैसे से हमारे यहां चुनाव नहीं होता। कांग्रेस के लोग देखें, जिन्होंने कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में लूट का अड्डा बना रखा था। लूट के पैसे पर पार्टी चलाने वाले लोग क्या बात करेंगे।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर

(केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ) ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

Main Portal: https: // eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-

स. क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	154068 प्रथम आमंत्रण 13.03.2024	कोडातराई पुसौर सूरजगढ़ मार्ग लंबाई 8.30 कि.मी. (कि.मी. 5 से 9 एवं 12/8 (100) से 15) का उन्नयन कार्य।	862.98
2	154078 प्रथम आमंत्रण 13.03.2024	रायगढ़ लोइंग महापल्ली जामगांव मार्ग लंबाई 8.60 कि.मी. (कि.मी. 21 से 29/6) का निर्माण कार्य।	541.17
3	154082 प्रथम आमंत्रण 13.03.2024	रा.रा. 200 से चपले से नंदेली पेण्ड्रवा चन्द्रपुर लंबाई 7.80 कि.मी. का मजबूतीकरण का कार्य।	562.70
4	154070 प्रथम आमंत्रण 13.03.2024	पुसौर रेंगालपाली मार्ग के कि.मी. 1 से 10= 10.00 कि. मी. में मजबूतीकरण का कार्य।	608.22
5	154073 प्रथम आमंत्रण 13.03.2024	बडे भण्डार उमारिया पुसौर रेंगालपाली मार्ग 7.425 कि.मी. में मजबूतीकरण का कार्य।	787.15
6	154074 प्रथम आमंत्रण 13.03.2024	कोंडातराई लोहरसिंग जोगीतराई मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का निर्माण कार्य।	381.66
7	154077 प्रथम आमंत्रण 13.03.2024	लोईंग महापल्ली में आई.टी.आई. भवन का निर्माण कार्य वा.स.से.फि विद्युतीकरण एवं पहुंच मार्ग सहित निर्माण कार्य।	341.42
8	154075 प्रथम आमंत्रण 13.03.2024	जिला रायगढ़ के कोयलंगा नाला में पुलिया निर्माण का कार्य।	273.02

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि सं.क्र. 01 से सं.क्र. 08 दिनांक 03.04.2024 निर्धारित है। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

मुख्य अभियंता
केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ
कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

जी-08550/10

सीएए के खिलाफ दुष्प्रचार देश हित में नहीं

अजय कुमार

भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के समय अपने घोषणापत्र में किये गये एक और वायदे को पूरा कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े देश में आचार संहिता लागू होने से कुछ दिनों पहले सीएए के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। बीजेपी इसे मोदी की गारंटी बता रही है। 2019 में बीजेपी ने कुछ जो बड़े वादे किये थे उसमें जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म किया जाना, अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण में आ रही बाधा को दूर करना, तीन तलाक को खत्म करने का कानून बनाना और अब सीएए को भी अमली जामा पहना दिया गया है। बीजेपी को तमाम चुनावों में करीब 8 प्रतिशत मुसलमानों ने ही वोट दिया, लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नजर आ रही है। सरकारी नुमांइदे कहते हैं कि देश में जिस तरह से तुष्टिकरण की सियासत को बढ़ावा दिया गया था, ऐसे में बीजेपी के लिये मुसलमानों का दिल जीतना आसान नहीं है। इसीलिये सीएए जैसे कानून की भी मुसलमानों के बीच मुखालफत होने लगती है, जबकि इसका भारत के किसी भी नागरिक से कोई लेना-देना ही नहीं है। सीएए किसी की नागरिकता लेने के लिये नहीं बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने वाला कानून है, जो अपने देशों में अल्पसंख्यक होने के कारण वर्षों से पीड़ित हो रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जब नागरिकता संशोधन बिल लाया गया तो इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुए थे। तब आंदोलन में शामिल मुस्लिमों का मानना था कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों को तो नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन मुसलमानों को यह सुविधा नहीं दी गई है। उनके मन में यह बात घर कर गई कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह रही कि 2019 के बाद हुए राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी मुसलमानों का पहले वाला वोटिंग पैटर्न कायम रहा। हालांकि, अब माहौल काफी बदल गया है। अपवाद को छोड़कर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु अपनी कौम को यह बता रहे हैं कि वह इस कानून को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं पालें, क्योंकि इससे किसी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं होगा। किसी की नागरिकता नहीं जायेगी, लेकिन ओवैसी जैसे नेता जरूर सीएए के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। यही वजह है कि भाजपा ने पसमांदा मुस्लिम समाज को साधने के लिए दो साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। योगी सरकार-टू में पसमांदा समाज के दानिश आजाद अंसारी को राज्यमंत्री बनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. तारिक मंसूर को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ विधान परिषद में भेजा गया। इतना ही नहीं स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और सभासद पद पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। वहीं कौमी चौपाल और स्नेह संवाद के जरिये भी मुस्लिमों के बीच मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जा रही हैं। यूपी में पीएम आवास में से लगभग 19 लाख आवास मुसलमानों को मिले। 2.61 करोड़ मुस्लिमों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। 2 लाख गरीब मुस्लिमों की शादी में आर्थिक मदद दी गई है। आयुष्मान भारत में 28, किसान सम्मान निधि में 22 और शौचालय निर्माण योजना में 23 फीसदी हिस्सेदारी मुस्लिमों की है। भाजपा के रणनीतिकार मुसलमानों को समझा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर न सिर्फ हज का कोटा बढ़वाया। मोदी सरकार ने ही 6 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के कागजातों का डिजिटलीकरण करवाने का काम किया है। वहीं सीएए को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी सदस्य इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुसलमानों से कहा कि सीएए पर अधिसूचना जारी होने पर नजरिया पेश करना अभी सही नहीं है।न्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सीएए को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें अमन बनाए रखें।

'एमवाई' का खेल बिगाड़ेगा 'डीएम'

संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी और उसकी सुप्रीमों मायावती के खिलाफ लगातार 'जहर' उगल रहे थे, जिसे बहनजी चुपचाप इकठा करती जा रही थीं, शायद वह सही समय का इंतजार कर रही होंगी। आज भले ही बसपा का जनाधार काफी घट गया है लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि बसपा समाप्त पार्टी बन गई है। मायावती की राजनैतिक सूझबूझ की आज भी कोई बराबरी नहीं है, जिन मायवती का पूर्व सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से वर्षो तक 36 का आकड़ा रहा, कई बार मुलायम को मायावती ने सियासी मैदान पर धूल चटाई थी,उन मायावती को अखिलेश कभी हल्के में नहीं लेते यदि समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास वह पढ़ लेते। इंडी गठबंधन में बसपा को नहीं शामिल करने के लिये जमीन-आसमान एक किये हुए अखिलेश यादव को मायावती ने उन्हीं की पिच पर पटकनी देने का मन बना लिया है। यह पिच मुस्लिम वोट बैंक की है जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को काफी नाज है,लेकिन बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिये सात में से पांच सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर समाजवादी पार्टी के एमवाई (मुस्लिम-यादव) वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर ली है। बता दें आज भले ही सपा-बसपा में भारी अदावत नजर आ रही हो लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव दोनों मिलकर लड़े थे। 2019 में संसद पहुंचने वाले उसके 10 सांसदों में तीन मुस्लिम थे। इस बार बसपा की रणनीति सपा-कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के संकेत दे रही है। बसपा सुप्रीमों की एक चाल ने 'सौ सुनार की, एक लुहार की' वाली कहावत चरितार्थ कर दी है।

दरअसल, पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पार्टी ने इसी रणनीति के तहत प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। अब तक घोषित किए गए उसके सात प्रत्याशियों में से पांच मुस्लिम हैं। हैरानी की बात यह है कि बसपा अपने किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट देने के मूड में नहीं दिख रही है। फिलहाल पार्टी के साथ अपनी आस्था जताने वाले बिजनौर से सांसद मलूक नागर की जगह विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। उनका मुकाबला रालोद के चंदन चौहान से होगा। यानी यहां जाट और गुर्जर मैदान में हैं, कांग्रेस-सपा का प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। उधर,कांग्रेस के खेमे में जा रहे अमरोहा के सांसद दानिश अली की जगह डॉ. मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। सहारनपुर के बसपा सांसद हाजी फजलुर्रहमान को कांग्रेस टिकट दे सकती है, लिहाजा बसपा ने माजिद अली को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं, पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर सीट पर दारा सिंह प्रजापति को बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरह मुरादाबाद में इरफान सैफी को, तो पीलीभीत में अनीस अहमद खां को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कन्नौज सीट पर अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट पर भाजपा के सुब्रत पाठक मैदान में हैं, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा है, जो उनके लिये खतरे की घंटी से कम नहीं है।

इतना ही नहीं बसपा एनडीए में भी सेंधमारी कर रही है,जिससे लोकदल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल रालोद के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने अचानक से पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छोड़ कर सबको हैरान कर दिया है। इससे पहले वह लोकदल के प्रसार में जुटे हुए थे। उन्होंने लोकदल को छोड़कर बसपा को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने मंगलवार को बीएसपी में शामिल होने की घोषणा बिजनौर के कार्यकर्ता सम्मेलन में की। इस कार्यकर्ता सम्मलेन में बीएसपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रभारी शमशुद्दीन राइन ने चौधरी विजेंद्र सिंह के बीएसपी की सदस्यता लेने की घोषणा की। मायावती ने चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने आगे कहा कि बहन जी सबसे पहले बिजनौर सीट से जीत दर्ज करके संसद पहुंची थी। चौधरी विजेंद्र सिंह ने अपने अस्पतालों व शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जनता की सेवा की है। जिसको देखते हुए बहन मायावती ने उन्हें बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया है। एक दो दिन में बीएसपी चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर सीट से लोकसभा सीट का टिकट देने की घोषणा कर सकती है। बिजनौर के जिलाध्यक्ष दलीप कुमार ने यह जानकारी दी थी कि एक दो दिन में पार्टी प्रमुख बहन मायावती उन्हें लोकसभा टिकट दे देंगी। वहीं चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान, मजदूर, गरीब सभी पिछड़ी जातियों समेत शोषित और वंचितों को उनका हक दिलाने का कार्य करेंगे।

चौधरी के बसपा की सदस्यता ग्रहण करने से पहले यहां बीजेपी-आएलडी गठबंधन की जीत पक्की समझी जा रही थी। दोनों ने गठबंधन के तहत रालोद विधायक चंदन चौहान को बिजनौर सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया था। चौधरी विजेंद्र सिंह की नजर भी जाट वोटों को साधने की थी, जो कि लोकदल को जीत दिलाने के मकसद से कार्य कर रहे थे। लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन के बाद इस सीट का समीकरण बदल जाने के कारण चौधरी विजेंद्र सिंह ने अपनी राह बदल ली और बीएसपी को ज्वाइन कर लिया। अब जब बीएसपी ने चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर सीट से प्रत्याशी बना दिया है तो वहां भाजपा-आरएलडी गठबंधन और बीएसपी के बीच चुनावी घमासान होने की संभावना है।

कुल मिलाकर मायावती के मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देने से बसपा को भले ही कोई फायदा न हो लेकिन इससे सपा को जरूर नुकसान हो सकता है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के बीते उपचुनाव को देखें तो सपा के प्रत्याशी रहे धर्मेन्द्र यादव को केवल इसीलिए हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि उनके सामने बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली को टिकट मिल गया था। इस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी।अब जरूर जमाली सपा में हैं और पार्टी ने उन्हें विधान परिषद सदस्य के लिये चुन लिया है। बता दें कई चुनावों में ये देखने को मिलता रहा है कि बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से सपा का एम-वाई फार्मूला कहीं हद तक असफल हो जाता है। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी सपा की जीत के लिए एक बड़ा रोड़ा बन जाते है। मायावती अपनी रणनीति के अनुसार मुस्लिमों पर फोकस करती रही हैं. वो लगतार ये समझाने का प्रयास करती हैं, कि दलित और मुस्लिम एक साथ आजाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का सिर्फ एक ही प्रत्याशी जीता था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बलिया जिले की रसड़ा सीट से उमाशंकर सिंह ने जीत हासिल की थी। अन्य सभी विधानसभा सीटों पर बसपा को हार का सामना करना पड़ा था। अब इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम चेहरों पर मायावती ने एक बार फिर दांव लगाया है। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की रणनीति कितनी कामयाब होती है। ऐसा लगता है कि बसपा सुप्रीमों मायावती ने यह तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी के एमवाई (मुस्लिम-यादव) वोटबैंक को धाराशायी करने के लिये उन्हें डीएम (दलित-मुस्लिम) को मजबूत करना ही पड़ेगा। दलित तो बसपा के साथ हैं ही,मुसलमानों को लुभाने के लिये ही मायावती बड़े पैमाने पर मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारने की रणनीति बना रही हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-33)

गतांक से आगे...

चाहे द्वादश आदित्य भी एक साथ मिलकर क्यों न तपने लगें; किन्तु फिर भी मन से विहीन मनुष्य को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती। केवल संकल्पहीनता रूपी एक साध्य ही सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति का साधन है। अत: तत्पद का आश्रय ग्रहण करके संकल्पहीनता के विस्तृत साम्राज्य में प्रतिष्ठित हो जाओ।

अचञ्चल मन कहीं पर नहीं दीखता, चञ्चलता मन का सहज धर्म है, जैसे अग्नि का सहज धर्म गर्मी प्रदान करना है। यही चञ्चल स्वभाव वाली स्पन्दन शक्ति चित्त का स्वाभाविक धर्म है। इसी मानसिक शक्ति को सांसारिक प्रपञ्च का सहजस्वरूप जानना चाहिए। जो मन अचञ्चल हो जाता है, वही अमृतस्वरूप कहा जाता है, वही तप है। उसे ही शास्त्रीय सिद्धान्त की दृष्टि से मोक्ष कहते हैं। मन की चञ्चलता ही अविद्या है और वासना उसका स्वरूप है। शत्रुरूपी वासना को सद्विचारों के द्वारा काट देना चाहिए।

हे निष्पाप मुने! मन को पुरुषार्थ के द्वारा जिस उद्देश्य में स्थिर करो, उसे प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि को अर्जित करो। अतएव प्रयासपूर्वक चित्त को चित्त से वशीभूत करके शोकरहित अवस्था के आश्रय से, आतंक से दूर रहकर शान्ति प्राप्त करो। विषय विकारों से रहित मन ही मन का पूर्णरूपेण निरोध करने में समर्थ हो सकता है।

किसी राजा को पराजित करने में कोई राजा ही समर्थ होता है। जो तृष्णारूपी ग्राह के द्वारा ग्रसित किये जा चुके हैं, जो संसार सागर में गिरकर भँवरों के जाल में फँसकर अपने लक्ष्य से दूर भटक गये हैं, उन्हें बचाने के लिए विषय-विकारों से रहित मन ही समर्थ है, वही नौका का रूप धारण करके पार लगा सकता है।

क्रमश: ...

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस

हर्षिता सक्सेना

हमारे आसपास मौजूद वायरस और बैक्टीरिया अक्सर हमें अपनी चपेट में लेकर बीमार कर देते हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन की मदद से इन संक्रामक बीमारियों से हम सुरक्षित रह पाते हैं। वैक्सीन वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी रक्षा करते हुए हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाती है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हम सब अपने लिए जरूरी वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसलिए लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व बताने के मकसद से हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है।

देश में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1995 में हुई थी। उस साल इसी दिन यानी 16 मार्च को भारत में मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। साथ ही इस दिन भारत को पोलियो मुक्त बनाने के मकसद से सरकार ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत 0 से 5 साल की उम्र के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दी गई थीं और इस अभियान के तहत साल 2014 में, भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था।

टीकाकरण का मनुष्य के जीवन में खास महत्व है। गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। टीकाकरण से खतरनाक बीमारी जैसे पोलियो, चेचक, टिटनस और खसरा आदि से बचा जा सकता है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण जरूरी है। वैक्सीनेशन के कारण संक्रमण को रोका जा सकता है। टीका लगवाने से आप तो सुरक्षित रहेंगे ही आपके साथ-साथ आपके आस-पास के लोगों की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी।

इस दिन की शुरुआत भले ही बच्चों की वैक्सीन के साथ हुई हो, लेकिन इसका महत्व सभी के लिए है। दरअसल, टीका सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं,बल्कि बड़े, बूढ़ों के लिए भी जरूरी होता है। ऐसे में लोगों को इसका महत्व समझाने से मकसद से इस दिन को मनाया जाता है। वैक्सीन कई खतरनाक और गंभीर बीमारियों को रोकने का एक प्रभावी माध्यम है। वैक्सीन के महत्व का सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान देखने को मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, हर साल टीकाकरण की मदद करीब 2-3 मिलियन लोगों की जान बचाई जाती हैं। आपको बताते चलें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2017 से लेकर साल 2020 तक अपने देश में करीब 32.4 करोड़ बच्चों को एमआर टीकाकरण किया जा चुका है।

टीकाकरण से वैश्विक महामारी से बचा जा सकता है। टीकाकरण से आप बीमारी को खत्म कर सकते हैं। टीकाकरण एक ऐसा जरिया है जो मूल रूप से संक्रमित रोगों को फैलने से रोकने का काम करता है साथ ही संक्रमित व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ानें में मदद करता है।

कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी क्या पलट देगी पूरा खेल?

अभिनय आकाश

मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त लाडली बहना कार्यक्रम जिसमें शिवराज सिंह की सरकार ने वादा किया था कि सभी बहनों को हर महीने पहले 1000, फिर 1250 रुपए और उसके बाद यह राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा। परिणामस्वरूप बीजेपी को राज्य में धमाकेदार जीत दर्ज की। वहीं पीएम मोदी की फ्री राशन स्कीम यानी पांच किलो अनाज वाले मुद्दे ने भी बीजेपी को कई राज्यों में लाभांवित किया है। वहीं इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में एक अदद जीत की आस के साथ चुनावी पिटारों से वादों की बरसात शुरू कर दी है। महिलाओं को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी का ऐलान किया है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 13 मार्च को नारी न्याय गारंटी का ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में आधा हक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 5 घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पांच वादे 2019 के चुनाव घोषणापत्र का एक ताज़ा संस्करण प्रतीत होता है। 2019 के आम चुनाव से पहले, कांग्रेस ने सत्ता में आने पर न्यूनतम आय सहायता कार्यक्रम या न्यूनतम आय योजना (न्याय) शुरू करने का वादा किया था। इसमें रुपये का नकद हस्तांतरण शामिल था। सभी भारतीय परिवारों में से सबसे गरीब 20 प्रतिशत (लगभग 5 करोड़ परिवार) को 72,000 प्रति वर्ष देने की बात कही गई थी। उस वक्त भी पार्टी ने कहा था कि जहां तक संभव होगा पैसा परिवार की किसी महिला के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। उस वक्त अर्थशास्त्री ज्यां ड्रेज़ ने न्याय के कारण कुल वार्षिक खर्च 3,60,000 करोड़ रुपये या भारत की जीडीपी का लगभग 2% होने का अनुमान लगाया था।

घोषित पांच वादों में से सबसे बड़ा, कम से कम वित्तीय निहितार्थ के संदर्भ में वादे को महालक्ष्मी कहा जाता है और इसमें एक गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपये हस्तांतरित करना शामिल है। हालाँकि, इसका लक्ष्य कितने गरीब परिवारों को लक्षित करना है, इसकी सटीक संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। जैसा कि हालात हैं, भारत का गरीबी अनुमान अलग-अलग पद्धतियों के आधार पर काफी भिन्न है। उदाहरण के लिए, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीबी अनुपात लगभग 11% आंका गया है, जबकि इसके सीईओ ने कथित तौर पर दावा किया है कि अगर पिछले महीने जारी उपभोग व्यय सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो गरीबी 5% तक कम हो सकती है। विश्व बैंक ने प्रति दिन 2.15 अमेरिकी डॉलर (या क्रय समता के संदर्भ में 48.9 रुपये) पर रहने वाले लोगों की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर 2022-23 में भारत का गरीबी अनुपात 11.3% आंका है। तो अगर कांग्रेस चालू वित्तीय वर्ष में महालक्ष्मी वादे को लागू करती है तो सरकार को कितना नुकसान होने की संभावना है? अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा का कहना है कि अगर सरलता के लिए कोई गरीबी अनुपात 10% मान लेता है, तो इसका मतलब है कि लक्षित लाभार्थी 14 करोड़ परिवार होंगे (कुल जनसंख्या 140 करोड़ मानते हुए)। यदि प्रत्येक गरीब परिवार से एक महिला को लक्षित किया जाए यानी 2.8 करोड़ महिलाएं तो कुल व्यय 2.8 लाख करोड़ रुपये होगा। यह 2024-25 में भारत की जीडीपी (328 लाख करोड़ रुपये) का 0.8% है (फरवरी में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अनुसार)। यदि गरीबी अनुपात 5% है, जैसा कि नीति आयोग का दावा है, तो व्यय सकल घरेलू उत्पाद का आधा यानी 0.4% हो जाएगा।

वित्तीय व्यय का अनुमान लगाने का एक अन्य तरीका सबसे गरीब परिवारों को लक्षित करना है- जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है -लाभार्थियों की कुल संख्या थोड़ी कम होगी। वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 2.33 परिवार। यदि उनमें से प्रत्येक की महिलाओं को 1 लाख रुपये मिलते हैं, तो कुल वार्षिक खर्च 2.33 लाख करोड़ रुपये होगा- या भारत की जीडीपी का 0.7%। दूसरा वादा - सभी सरकारी रिक्तियों में से आधी महिलाओं के लिए आरक्षित करने का कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही मौजूद रिक्तियां हैं।

आशा, आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन तैयार करने में शामिल महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार के योगदान को दोगुना करने का - सामाजिक कल्याण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अर्थशास्त्री दीपा सिन्हा के अनुसार, छोटा ही सही, कुछ वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। . ऐसा इसलिए है क्योंकि वेतन स्तर काफी कम है। पिछले साल मार्च तक, 10.5 लाख आशा कार्यकर्ता, 12.7 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 25 लाख से अधिक मिड-डे मील रसोइये थे। सिन्हा का कहना है कि इन तीनों समूहों को क्रमश: लगभग 2,000 रुपये, 4,500 रुपये और 1,000 रुपये का मासिक वेतन मिलता है। उदाहरण के लिए, 2021-22 में, केंद्र ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन पर 8,908 करोड़ रुपये खर्च किए - और वे तीनों की तुलना में सबसे अधिक वेतन अर्जित करते हैं। इन राशियों को दोगुना करना मान लीजिए कुल 54,000 करोड़ रुपये अभी भी भारत की जीडीपी (328 लाख करोड़ रुपये) का काफी नगण्य प्रतिशत है।

हर पंचायत में महिलाओं के अधिकारों के लिए कानूनी सलाहकारों (अधिकार मैत्री) की नियुक्ति के सटीक वित्तीय बोझ का अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि पारिश्रमिक को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। प्रत्येक जिले में कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण की लागत का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। मेहरोत्रा बताते हैं कि ये हॉस्टल मुफ्त नहीं हैं। दूसरे शब्दों में उनकी परिचालन लागत यकीनन कामकाजी महिलाओं द्वारा स्वयं वहन की जा सकती है। जहां तक बिल्डिंग की लागत की बात है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि ये हॉस्टल कितने बड़े हैं।

भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या दोगुनी की जाएगी। इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय घोषित किए हैं। और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। यही हमारा 1926 से अब तक का रिकार्ड है, जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम मेनीफेस्टो बना रहे हैं, और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। आप सब अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देते रहिए और लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस लड़ाई में हमारा हाथ मज़बूत करिए।

आज का इतिहास

1966 अमेरिका ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान जेमिनी 8 लांच किया।
1968 वियतनाम युद्ध-अमेरिकी सैनिकों ने सोन एम में सैकड़ों निहत्थे लोगों को मार डाला दक्षिण वियतनाम के सोन टी जिले में गाँव।
1970 नई अंग्रेजी बाइबल प्रकाशित की गई।
1976 आठ सालों तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और 13 वर्षों तक लेबर पार्टी के नेता रहे, हैरल्ड विल्सन ने त्यागपत्र देकर सबको चौंका दिया था।
1978 इटली के पूर्व प्रधान मंत्री एल्डो मोरो को रोम में मारियो मोरेटी और रेड ब्रिगेड द्वारा अपहरण कर लिया गया था।
1984 विलियम बकले, लेबनान के बेरुत में सीआईए स्टेशन प्रमुख, इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा धोखेबाजी की गई।
1988 ईरान-इराक युद्ध: इराकी बलों ने 5, 000 लोगों की हत्या करते हुए रासायनिक हथियारों के साथ हलाजा के कुर्द शहर पर हमला करना शुरू कर दिया।
1989 मिस्र में चिपोज के पिरामिड में 4400 साल पुरानी ममी मिली।
1995 नासा अंतरिक्ष यात्री नॉर्मन रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मीर का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी बने।
1995 भूपिंदर सिंह ने वर्ल्ड कप इतिहास में रिकॉर्ड बनाया। जैसा कि उनके साथ पी। धर्माणी थे और दोनों ने 7 वें विकेट के लिए 461 रन बनाए।
1996 फ्रैंक ब्रूनो को हराकर नाइक टायसन ने फिर से विश्व चैम्पियनशिप जीती। मैच केवल 2 राउंड तक जारी रहा।
1997 स्टुअर्ट Appleby ने होंडा गोल्फ क्लासिक जीता।
2003 अमेरिकी शांति कार्यकर्ता राशेल कोरी को राफाह में इजरायल के रक्षा बलों के बख्तरबंद बुलडोजर से कुचल दिया गया था क्योंकि वह एक घर को ढहा रही थी।
2006 संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के गठन के लिए सर्वसम्मति से वोट दिया।
2006 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को भारी मात्रा में वोट दिया।
2007 एक ओवर में छह छक्के लगाकर दक्षिण अफ्रीका के हर्शेल गिब्स ने विश्व रिकार्ड बनाया।
2010 लाल रक्त सरकार के द्वार पर फैला है। यह थाई लाल शर्ट द्वारा किया गया था जिसने विरोध के तीसरे दिन इसे किया था।
2011 अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने एक भयानक बयान दिया। यदि वह राष्ट्रपति ओबामा के फिर से चुने जाने पर सेवानिवृत्त होंगे। उसने कहा कि उसने दूसरा कार्यकाल नहीं जीता है।

क्या केंद्र के बनाए कानून को राज्य लागू करने से कर सकता है इनकार?

अभिनय आकाश

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर कहीं जश्न कहीं विरोध यानी दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शरणार्थी बस्ती में जश्न का माहौल नजर आया। पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थी एक-दूसरे को रंग लगाते और मिठाइयां खिलाते नजर आए। वहीं दिल्ली से किलोमीटर की दूरी पर केरल की राजधानी तिरुअंतपुरम में एलडीएफ के कार्यकर्ता सीएए के विरोध में इस कानून की प्रतियां जलाते नजर आए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सीएए के नोटिफिकेशन जारी होते ही कह दिया कि था कि वो अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि उनके अपने राज्य में सीएए लागू नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी इसे विभाजनकारी बताया। इसके साथ ही इसे तमिलनाडु में भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल ये रिपोर्ट लिखे जाने तक विपक्षी शासित तीन राज्यों ने इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल की क्या केंद्र के बनाए किसी कानून को राज्य अपने यहां लागू करने से रोक सकता है? इसके साथ ही आपको नागरिकता के सवाल पर संविधान सभा में हुई जबरदस्त बहस के बारे में भी बताएंगे।

घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात मोदी सरकार द्वारा समय-समय पर की भी जाती रही है। इस दिशा में सबसे पहले असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस पर काम हुआ। वर्तमान में नागरिकता संशोधन विधेयक को भी इसी कवायद का हिस्सा माना गया। संसद में पारित होने के पांच साल बाद केंद्र ने 11 फरवरी को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू कर दिया। इस संशोधन के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को नागरिकता का प्रावधान है जो पलायन करके भारत आए। इनमें हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी लोग शामिल हैं। नागरिकता संशोधन कानून किसी एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश में शरणार्थियों पर लागू हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि सबकुछ एकदम क्लीयर है तो फिर मामला कहां फंस रहा है? दरअसल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे कई राज्यों का कहना है कि वे अपने-अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगे।

कोई भी राज्य सरकार संसद द्वारा पारित कानून की मंशा या वैधता पर सवाल उठा सकती है। जिसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके लिए संविधान के भीतर और लोकतंत्र के दायरे में अनेक प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कानून को चुनौती दी जा सकती है। संसद अपने द्वारा पारित किसी कानून को रद्द कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किसी कानून को रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सीएए से जुड़े 200 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। जिस पर सुनवाई होनी है। लेकिन कानून के जानकार बताते हैं कि इस बीच में अगर किसी राज्य सरकार को इसको लेकर आपत्ति है तो भी उन्हें इस कानून का पालन करना होगा।

24 अप्रैल 1973 को भारत की सर्वोच्च अदालत ने केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस फैसले को भारत के कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। 13 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। न्यायालय ने तय किया कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने का अधिकार है, किन्तु वह किसी भी सूरत में

संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकते। बुनियादी ढांचे का मतलब है संविधान का सबसे ऊपर होना, कानून का शासन, न्यायपालिका की आजादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, सरकार का संसदीय तंत्र, निष्पक्ष चुनाव आदि। कानून का शासन बेसिक स्ट्रक्चर है। कानून का शासन का मतलब ये है कि कोई भी कानून बना है वो सभी पर बाध्यकारी है। संविधान की शपथ लेते हैं सभी लोग। संविधान के आर्टिकल 246 में संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों को वर्गीकृत किया गया है। सहमति अहसमति का मतलब नहीं रह जाता है। कानून की वैधता के लिहाज से देखें तो सातवीं अनुसूति, नागरिकता के सवाल के तहत केंद्र सरकार को पूरे अधिकार हैं। ऐसे 97 विषय हैं, जिन्हें संघ सूची की 7वीं अनुसूची के अधीन हैं, जिनमें रक्षा, विदेश मामले, रेलवे और नागरिकता आदि शामिल हैं। नागरिकता किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है और अमेरिका यूरोप में भी बदलाव किया गए हैं। इसके अलावा किसी दूसरे धर्म के लोगों को नागरिकता देने से मना नहीं किया गया है। नेताओं ने अभी तक बयान दिए हैं और राज्य सरकार की तरफ से कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया है।

नागरिकता कैसे प्रदान की जाए, इस सवाल पर लंबी बहस हुई और आखिरकार, संविधान निर्माताओं ने इस प्रक्रिया से धर्म को नहीं जोड़ने का फैसला किया। यहां संविधान सभा की बहस के दौरान दिए गए कुछ बयान दिए गए हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे कुछ सबसे जटिल मुद्दों को उठाया गया और हल किया गया। जैसा कि आज तर्क दिया जा रहा है, संविधान सभा के कुछ सदस्यों का मानना ??था कि सभी हिंदुओं और सिखों के पास भारत में एक प्राकृतिक घर होना चाहिए, क्योंकि उनके पास %अपना कहने के लिए कोई अन्य देश नहीं था%। मध्य प्रांत और बरार के कांग्रेस सदस्य पीएस देशमुख ने 11 अगस्त, 1949 को विधानसभा में कहा कि यहां हम हजारों वर्षों के इतिहास के साथ एक संपूर्ण राष्ट्र हैं और इस तथ्य के बावजूद, हम इसे त्यागने जा रहे हैं। न तो हिंदू और न ही सिख के पास व्यापक दुनिया में जाने के लिए कोई अन्य जगह है। केवल इस तथ्य से कि वह हिंदू या सिख है, उसे भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए क्योंकि यही एक परिस्थिति है जो उसे दूसरों के प्रति नापसंद बनाती है। लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं और इस तथ्य को मान्यता नहीं देना चाहते कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हर हिंदू या सिख के पास अपना घर होना चाहिए। यदि मुसलमान अपने लिए पाकिस्तान नामक एक विशेष स्थान चाहते हैं, तो हिंदुओं और सिखों को भारत को अपना घर क्यों नहीं बनाना चाहिए?

हालाँकि, मध्य प्रांत और बरार के एक पारसी कांग्रेसी आरके सिधवा ने बताया कि यह सुविधा केवल हिंदुओं और सिखों तक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। केवल सिखों और हिंदुओं का उल्लेख करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि हमें आवश्यक रूप से %किसी समुदाय% का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे हम अन्य समुदायों की अनदेखी कर रहे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज पाकिस्तान में लाखों पारसी और ईसाई हैं जो वापस आना चाहते हैं आपको उनके खिलाफ दरवाजा क्यों बंद करना चाहिए?

संयुक्त प्रांत के जसपत रॉय कपूर की राय थी कि एक बार जब किसी ने पाकिस्तान से अपना रिश्ता जोड़ लिया, तो उसे वापस नहीं आने दिया जाना चाहिए। इस संशोधन में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, यदि 19 जुलाई, 1948 के बाद, वे हमारे दूतावास या उच्चायुक्त से वैध परमिट प्राप्त करने के बाद भारत वापस आए, तो उनके लिए खुद को नागरिक के रूप में पंजीकृत कराना खुला होना चाहिए। इस देश का. यह सिद्धांत का गंभीर मामला है। एक बार जब कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला जाता है और अपनी वफादारी भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित कर लेता है, तो उसका प्रवास पूरा हो जाता है। इस पर, बिहार के ब्रजेश्वर प्रसाद ने बताया कि पाकिस्तान जाने वाले सभी लोग वहां बसना नहीं चाहते थे, और कुछ लोग हिंसा भड़कने के कारण घबराहट में भाग गए थे।

1949 में भी पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से प्रवासन के कारण असम की जनसांख्यिकी बदलने को लेकर चिंताएँ थीं। पूर्वी पाकिस्तान के पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा, मुझे एक विश्वसनीय प्राधिकारी ने बताया है... कि विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से तीन गुना अधिक हिंदू शरणार्थी, मुस्लिम असम में चले गए हैं।

एमएसपी गारंटी देनी है तो पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा

दिनेश कुलकर्णी

आजकल देश में ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका सहित कई देशों में किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। सब जगह समान मुद्दा है कि खेती करना आर्थिक दृष्टि से अब फायदे का सौदा नहीं रह गया है। लागत बढ़ती जा रही है और उपज के दाम में अस्थिरता है। भारत के किसानों की मुख्य समस्या उपज की कम कीमत है। कृषि उत्पादों की कीमतें सरकारें अपने हिसाब से शुरू से ही तय करती रही हैं। जब देश में अनाज की कमी थी, तब सरकारें कुछ कीमत तय कर किसानों से जबरदस्ती खरीद कर लेती थीं। वही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की शुरुआत थी। जब सरकार की जरूरत केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक सीमित हो गई, तो उसने उसके लिए अनाज खरीदने की जिम्मेदारी ली और बाकी के लिए किसानों को बाजार भरोसे छोड़ दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केवल धान-गेहूं पर ही विचार किया गया। फिर उसकी अधिकतर खरीद पंजाब-हरियाणा से होने लगी। इसके परिणाम सामने हैं। पंजाब-हरियाणा में जमीन की उपजाऊ क्षमता काफी घट गई है और फसलों का विविधीकरण खत्म हो गया। इससे किसान को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। वह कर्ज में डूब गया। विडंबना है कि जिस राज्य से ज्यादा खरीद होती थी, वहां का किसान ज्यादा आक्रोशित है। पिछले 10 वर्षों में सरकार एमएसपी में बढ़ोतरी कर रही है। पंजाब, हरियाणा के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी सरकारी खरीद बढ़ी है। किंतु देशभर के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। सरकार ने गेहूं-चावल के साथ ही दलहन-तिलहन की भी एमएसपी बढ़ाई है। मगर उसकी खरीद की व्यवस्था न होने के कारण बहुत बार किसान को एमएसपी के नीचे ही उपज बेचनी पड़ती है। इन हालात में एमएसपी में बढ़ोतरी का भी फायदा किसान को नहीं मिलता। कारण, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं खेती में लगने वाली चीजों की कीमत पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इन चीजों और मजदूरी में औसतन दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। बीज, उर्वरक, कीटनाशकों के दामों में भी भारी वृद्धि हुई है। उत्पादक होने के बावजूद किसान को इन चीजों पर जीएसटी भी भरनी पड़ती है, जो जीएसटी की मूल अवधारणा के विपरीत है। किसान को यह जीएसटी वापस मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण उसकी जो लागत बढ़ी है, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा ही आती है। किसानों की मांग ऐसी एमएसपी की है, जो लाभकारी हो। अपने यहां छोटे और मझोले किसान सबसे ज्यादा हैं। उसके पास बेचने के लिए एक-दो फसल के अलावा अनाज होता ही नहीं। वे चाहते हैं कि कीमत मिलने का कुछ पक्का बंदोबस्त हो। वही गारंटी उसे चाहिए। सरकार कीमत तो घोषित करती है, पर वही कीमत उसे मिले, इसकी वह जिम्मेदारी नहीं लेती। साथ ही सरकार की आयात-निर्यात नीति भी इस समस्या को बढ़ाती है। आज अनेक विद्वान इस चिंता में दुबले हो रहे हैं कि समर्थन मूल्य की गारंटी देना संभव नहीं और देश की अर्थव्यवस्था पर इससे बोझ बढ़ेगा। किसान की साधारण, न्यायसंगत अपेक्षा यही है कि उसकी लागत पर लाभ जोड़कर उसे कीमत मिले। और उसे इससे कम कीमत पर उपज न बेचनी पड़े। यह बात नीतिकारों और विद्वानों को समझनी होगी। इस मसले का रास्ता ढूंढना होगा। किसान को कीमत की गारंटी देने के लिए हमें कई तरह के उपाय करने होंगे। सरकारी खरीद के साथ एक पूरा तंत्र विकसित करना होगा।

कमलनाथ ने कांग्रेस हाईकमान की अनदेखी का खामियाजा भुगता

हरीश गुप्ता

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गांधी परिवार के 60 वर्षों तक बेहद लाड़ले थे और उन्होंने इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र का दर्जा हासिल कर लिया था। कमलनाथ उन खास लोगों में थे जो दून स्कूल में राजीव तथा संजय गांधी के सहपाठी थे और छुट्टी के दिनों में पं। जवाहरलाल नेहरू के तीन मूर्ति आवास में रहा करते थे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब दून स्कूल क्लब की तूती बोलने लगी थी। कमलनाथ संभवत: इस क्लब के अंतिम सदस्य हैं, जिन्होंने टिकट वितरण के वक्त अभा कांग्रेस कमेटी के मप्र के प्रभारी चाहे वह जयप्रकाश अग्रवाल रहे हो या रणदीप सुरजेवाला की नहीं सुनी और गांधी परिवार की नजरों से गिर गए। अंतत: कांग्रेस मप्र विधानसभा का चुनाव हार गई और राहुल गांधी ने उन्हें नतीजे आने के 24 घंटे के भीतर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया।

नाराज होकर कमलनाथ ने भाजपा में जाने की कोशिश की मगर यह दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ को मप्र का मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ राहुल गांधी हमेशा रहे लेकिन सोनिया गांधी की ही चली। यह हमेशा संदेह किया जाता रहा कि मोदी सरकार कमलनाथ के प्रति नरम रही और उसने पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े पुत्र बकुल नाथ के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

बकुल नाथ अमेरिका में बसे भारतीय आप्रवासी (एनआरआई) हैं और उनका नाम अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे से लाभ अर्जित करनेवालों की सूचनी में आया था। जनवरी 2019 में जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई से राजीव सक्सेना का प्रत्यर्पण करवाया था, तब इस सौदे में बकुल नाथ का नाम सामने आया था। सक्सेना तीन हजार करोड़ रु. के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में एक बिचौलिया था। ईडी में सक्सेना का जो बयान दर्ज है, वह एक हजार पन्नों से ज्यादा का है और सौदे में सुशेन मोहन गुप्ता, कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी, बेटे बकुल नाथ आदि की संलिप्तता पर रोशनी डालता है। रतुल पुरी को इडी ने 2019 में गिरफ्तार किया था। इस सौदे से मिली दलाली की रकम सावन्ना ट्रस्ट के स्वामित्व वाली एक कंपनी के जरिए

हस्तांतरित की गई थी। इस सौदे के एक लाभार्थी बकुल नाथ पिछले पांच वर्षों से भारत नहीं आ सके हैं। कमलनाथ ने इस सौदे में किसी भी प्रकार की अनियमितता से इनकार किया था। उन्होंने इसमें अपनी भागीदारी का भी खंडन किया था। बहरहाल कमलनाथ के छोटे पुत्र और लोकसभा सदस्य नकुलनाथ को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में फिर से मैदान में उतारा है। यह सीट कमलनाथ के लिए 'करो या मरो' की स्थिति पैदा कर चुकी है। भाजपा की दिग्गज नेता मीनाक्षी लेखी में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की सारी खूबियां मौजूद हैं। वह प्रसिद्ध अधिवक्ता पी एन। लेखी के बेहद सम्मानित परिवार की सदस्य हैं। पी एन। लेखी अदालतों में अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की ओर से मुकदमे लड़े हैं एवं पार्टी में उनका बड़ा सम्मान रहा।

मीनाक्षी लेखी पार्टी की वफादार नेता रही हैं तथा कुशल वक्ता भी हैं। पार्टी में वह तेजी से उभरीं और प्रतिष्ठापूर्ण नई दिल्ली संसदीय सीट से 2014 में भाजपा की प्रत्याशी बनी। दिवंगत अरुण जेटली सहित भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम की सिफारिश की थी और उम्मीदों पर खरी उतरते हुए भी मीनाक्षी ने बड़े बहुमत से चुनाव जीत भी लिया। लोकसभा में उन्होंने अपने प्रदर्शन से अलग छाप छोड़ी और भाजपा ने 2019 के चुनाव में उन्हें फिर मौका दिया। मोदी सरकार में उन्हें विदेशी मामलों तथा संस्कृति विभाग का राज्यमंत्री भी बनाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने वरिष्ठ सहयोगी तथा विदेश मंत्री एस. जयशंकर से उनकी नहीं पटी। वह कार्यकर्ताओं को भी घंटों प्रतीक्षा करवाने लगी थीं, सफलता शायद उन्हें पच नहीं रही थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आलाकमान से उनकी शिकायत करना शुरू कर दिया था। उनका सितारा डूबने लगा और वह इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा का टिकट पाने में विफल रहीं। उनकी जगह एक अन्य महिला वरिष्ठ पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सुपुत्री बांसुरी स्वराज क्षितिज पर उभरी जिन्हें मीनाक्षी की जगह पार्टी ने टिकट दिया है। बांसुरी के साथ अपनी माता दिवंगत सुषमा स्वराज की विरासत भी है। मीनाक्षी लेखी अब पार्टी में अपने पुनर्वास का इंतजार कर रही हैं। वह अपनी करनी के चलते दौड़ से बाहर हुई हैं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू का चयन आश्चर्यजनक था। वह इस पद की दौड़ में दूर-दूर तक नहीं थे। उन्हें राहुल तथा प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता था। वह वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के भी नजदीकी सहयोगी थे। आनंद शर्मा को हालांकि राहुल गांधी पसंद नहीं करते, मगर वह सोनिया गांधी के भरोसेमंद हैं। जब कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जीता, तब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के दावे को पछाड़ते हुए सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया गया। गांधी परिवार ने हिमाचल में कांग्रेस सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने एक और भरोसेमंद सिपहसालार राजीव शुक्ला को राज्य का प्रभारी बनाकर भेजा।

चुनाव में चूंकि कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीत ली थीं, अत: सुक्खू और शुक्ला को लगा कि सरकार के लिए भाजपा कोई खतरा पैदा नहीं कर सकेगी। परंतु जो सोचा नहीं, वह हो गया। सुक्खू तथा शुक्ला ने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ही पार्टी के 6 विधायक राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। अगर सुक्खू आत्ममुग्ध थे, तो शुक्ला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए थे। उन पर उत्तर प्रदेश तथा गांधी परिवार को संभालने का भी जिम्मा था। बेचारे सुक्खू को इन सबकी कीमत चुकानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को नुकसान हो सकता है क्योंकि भाजपा को जीत की गंध आ गई है। सुक्खू के दिन अब इने-गिने रह गए हैं।

क्षेत्रीय नेताओं के लिए करो या मरो की स्थिति

प्रभु चावला

अगर शांतिकाल में कोई 'युद्ध' होता है तो वह चुनाव के दौरान होता है। एक वह दौर था, जब दरबारी ज्योतिषियों द्वारा बताई गई ग्रहों की गणना के आधार पर राजा हमला करने का समय चुनते थे। विडंबना यह है कि हालात बदलने के बावजूद वे नहीं बदलते। शक्तिशाली उद्योगपति, बाजार के जानकार, विचारधारा से ग्रस्त बुद्धिजीवी की कॉकटेल पार्टियों या टेलीविजन अपने लक्षित दर्शकों की भूख मिटाने के लिए आंकड़ों के खेल में जुट जाते हैं। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो नेताओं के उत्थान, पतन, हाशिए पर जाने और दौड़ से बाहर हो जाने की भविष्यवाणियां करना लोगों का शौक बन गया है।

2024 के लोकसभा चुनाव मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी तक सीमित नहीं है बल्कि उनमें ममता बनर्जी, शरद पवार, एम.के. स्टालिन, सिद्धारमैया और रेवंत रेड्डी की क्षेत्रीय विचारधाराओं के राजनीतिक स्थायित्व की भी परीक्षा होगी। यादवकुल रत्नों अखिलेश तथा तेजस्वी यादव को यह साबित करना होगा कि वे दिग्गज पिताओं के योग्य उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने अपने राज्यों में अपना जबर्दस्त मुकाम बनाया तथा प्रधानमंत्री को गद्दी पर बैठाने या उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

अब देखें 2024 के मुकाबले में कौन अपना अस्तित्व बचा पाता है। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे 50 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भविष्य तय करेंगे जिनके पिता मुलायमसिंह यादव की विराट शख्सियत की बदौलत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार लोकसभा की 36 तथा विधानसभा की लगभग 60 प्रतिशत सीटें जीतने में सफल हो गई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश विजयी हुए थे मगर उसके बाद उनका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। मायावती अकेले लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। उनकी 'अबूझ' राजनीति के चलते क्या अखिलेश उ.प्र. में

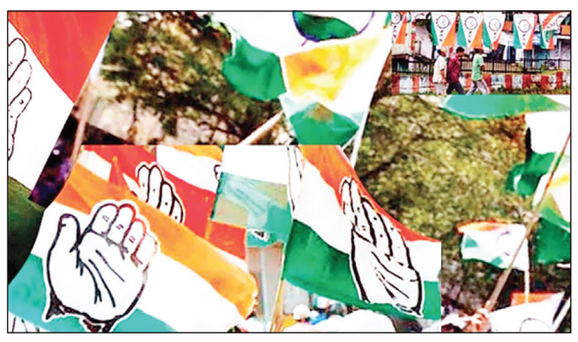

अपने सांसदों की संख्या मौजूदा 5 से बढ़ा सकेंगे और कांग्रेस के सांसदों की संख्या बढ़ाने में भी मदद कर पाएंगे।

बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहां भी परिवारवाद दांव पर लगा हुआ है। राज्य के 34 वर्षीय पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या तो अपने दिग्गज पिता लालूप्रसाद यादव के योग्य उत्तराधिकारी साबित होंगे या उनकी राजनीति का सूर्य भी डूब जाएगा। लालूप्रसाद की बिहार की राजनीति पर दबदबा रहा है। इस वक्त लोकसभा में यादव परिवार के राष्ट्रीय जनता दल का एक भी सदस्य नहीं है. इस मर्तबा मोदी के प्रभाव को कम करने की चुनौती तेजस्वी के सामने है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं।

राज्य में मराठा दिग्गज शरद पवार तथा शिवसेना के एक गुट का नेतृत्व कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की राजनीति में प्रासंगिकता दांव पर लगी हुई है। ये दोनों नेता राष्ट्रीय राजनीति के भी खिलाड़ी हैं। दोनों ही नेता हाल ही में अपनी-अपनी पार्टी को दो फाड़ होते देख चुके हैं और उनकी मूल पार्टी के चुनाव चिह्न और नाम विरोधी खेमे को मिल चुके हैं। 2024 के चुनाव में यह साबित हो जाएगा कि ये दोनों नेता अपने कार्यकर्ताओं तथा संगठन का समर्थन फिर से हासिल कर पाते हैं या नहीं? पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी तथा प्रधानमंत्री मोदी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का मैदान बन गया है। आगामी चुनाव प. बंगाल में ममता तथा भाजपा दोनों का भविष्य तय कर देंगे। यही नहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे का आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी ममता और भाजपा को उनके भविष्य का संकेत दे देंगे। तमिलनाडु में 71 वर्ष के एम.के. स्टालिन अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना कर रहे हैं। भाजपा इस चुनाव में सनातन के हथियार के साथ उतर रही है। ऐसे में स्टालिन को नया द्रविड़ शस्त्र ढूंढना होगा।

केरल ने अभी तक भाजपा के किसी प्रत्याशी को लोकसभा में नहीं भेजा है। राज्य में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले एलडीएफ तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ के बीच ही मुकाबला होता आया है। पहली बार केरल में इन दोनों गठबंधनों को भाजपा से कड़ी टक्कर मिल रही है। वामपंथी मोर्चा पूरी तरह मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के करिश्मे पर निर्भर है। क्या राज्य में विजयन की उम्मीदें ध्वस्त होंगी और भाजपा के लिए दरवाजे खुलेंगे?

मोदी का रथ रोकने के लिए लोकसभा चुनाव में नजरें कर्नाटक, झारखंड, पंजाब तथा दिल्ली में स्थानीय नेतृत्व की क्षमता पर टिकी हुई हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तथा उपमुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार भाजपा का आंकड़ा मौजूदा 25 से घटाकर 15 तक लाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। वे कांग्रेस की सीटें एक से बढ़ाकर 10 करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 'आप' के मुखिया अरविंद केजरीवाल तथा उनके साथी भगवंत मान पंजाब और दिल्ली में भाजपा को शून्य पर लाने के लिए कमर कसे हुए हैं।

कांग्रेस अकेले 17वीं लोकसभा का गणित और नए भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजे क्षेत्रीय नेताओं तथा जातिगत राजनीति का भाग्य तय करेंगे। चुनाव के केंद्र में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। दांव पर वंशवाद तथा वैचारिक स्थिरता और दिग्गजों की मजबूत विरासत होगी।

पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के हित में है संशोधन

हरबंश दीक्षित

नागरिकता संशोधन कानून की नियमावली लागू कर दी गई है। इसमें इस कानून के तहत आवेदन करने और उसकी जांच तथा फिर नागरिकता मिलने की प्रक्रिया बताई गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पोर्टल भी सृजित कर दिया है, जिस पर नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के सताए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में सम्मानजनक ठौर मिल सकेगा। करीब चार साल पहले ही इसे पारित किया गया था। हालांकि लगातार इसके बारे में भ्रम फैलाया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा पुष्टि के बाद भी यह थमा नहीं है। इससे न तो किसी की नागरिकता को कोई खतरा है और न ही अन्य लोगों द्वारा नागरिकता पाने की पुरानी प्रक्रिया में कोई बदलाव हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो लोग 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत आ चुके हैं और भारत में पांच वर्ष तक रह चुके हैं, तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। उन्हें नागरिकता पाने का अधिकार दिया गया है। कुछ विपक्षी दल तथा लोग इसे संविधान विरोधी कह रहे हैं। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 में उपलब्ध आस्था के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 में उपलब्ध दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कुछ लोग इसे मुस्लिमों के साथ भेदभाव मानते हैं, क्योंकि उन्हें इस कानून में मिलने वाले अधिकार से वंचित रखा गया है। उनका कहना है कि यह समता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। समानता का नियम कोई जड़ अवधारणा नहीं है। न्याय के दूसरे सिद्धांत की तरह इसमें भी देश, काल, परिस्थितियों के मुताबिक संशोधन और परिवर्द्धन होता रहता है। समता के सिद्धांत की मूल अवधारणा यह है कि समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। यदि अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक जैसा मानकर सबके लिए समता का सिद्धांत लागू कर दिया जाए, तो हम अन्याय को ही पोषित करेंगे। इसलिए समता के सिद्धांत में अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के लिए अलग नियम को मान्यता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया समानता का अधिकार भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि किसी के साथ भेदभाव न हो। किंतु समता के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए यह अनुच्छेद तार्किक वर्गीकरण की अनुमति देता है। भेदभाव और तार्किक वर्णीकरण के अंतर को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने सिद्धांत दिया है कि इसके लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहला कि वर्गीकरण का अधार स्पष्ट होना चाहिए, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके कि किसे सुविधा पाने वालों की श्रेणी में और किसे उससे बाहर रखा गया है। दूसरी शर्त यह है कि वर्गीकरण के आधार पर और उससे हासिल होने वाले उद्देश्य के बीच तार्किक संबंध हो। यानी वर्णीकरण करने वाले को यह साबित करना होगा कि उक्त वर्गीकरण से उसके न्यायपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति होगी। नागरिकता संशोधन कानून में तीन पड़ोसी देशों के छह मतावलंबियों को नागकिता देने का प्रस्ताव है। चूंकि दोनों आधार स्पष्ट हैं। उन्हे समझना आसान है, इसलिए अनुच्छेद 14 में अनुमन्य तार्किक वर्गीकरण की शर्त पूरी होती है। इसमें बताया गया है कि बीते वर्षों में इन पड़ोसी देशों में लाखों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई तथा पारसी समाज के लोग पूजा-पद्धति के आधार पर प्रताड़ित किए गए और उन्हें मजबूर होकर अपना देश छोड़ना पड़ा। इसलिए उन्हें न्याय देने के लिए इसे लाया गया है। इन तीनों देशों में गैर-मुस्लिमों के साथ भेदभाव के पर्याप्त प्रमाण हैं। अत: वहां के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने से इस कानून के उद्देश्य की पूर्ति होती है, इसलिए यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता। विधेयक के विरोधियों को इसे मुस्लिम, गैर-मुस्लिम बनाने के बजाय इसे गैर-प्रताड़ित और प्रताड़ित मानने की जरूरत है।

कई फायदे सिंगलहुड के

सक्सैसफुल कैरियर वूमन आजकल सिंगल रहना पसंद कर रही हैं. उन के फ्यूचर प्लान में शादी शब्द के लिए जैसे कोई स्थान ही नहीं रह गया है. लड़कियां अपनी सक्सैस, पावर, पैसा और आजादी को खुल कर ऐंजौय कर रही हैं. बेशक युवतियों में लेट मैरिज या नो मैरिज वाले सिंड्रोम से समाज या परिवार पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को ले कर मातापिता, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक व डाक्टर चिंतित हैं, लेकिन युवतियां खुश हैं. वाकई बड़े फायदे हैं सिंगल रहने के. यकीन न हो तो आगे पढ़ लीजिए

1. कैरियर में ऊंचा मुकाम

अपनी रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए काफी प्रयास, ऊर्जा व समय खर्च करने की जरूरत होती है. जाहिर सी बात है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप को ये सब करने की जरूरत नहीं है और आप अपनी सारी ऐनर्जी, समय, अटैंशन, काबिलीयत को अपने प्रोफैशन, कैरियर पर फोकस करती हैं, जिस से आप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. साथ ही, आप लेट नाइट मीटिंग, बिजनैस डिनर और औफिशियल टूर के लिए भी हमेशा तत्पर रहती हैं. अपनी कंपनी, औफिस के लिए भी पूरी तरह समर्पित रहती हैं. तो जाहिर सी बात है कि आप के लिए प्रमोशन की राह आसान हो जाती है.

2. जो चाहें वह करें

चूंकि आप को हर पल यह नहीं सोचना पड़ता कि आप का पार्टनर क्या पसंद करता है और क्या नहीं, आप बड़ी आसानी से वह सब कर सकती हैं, जो आप करना चाहती हैं. जिंदगी के हर पल को जी भर कर जी सकती हैं और वह भी बिना किसी अपराधबोध के. जैसे आप कालेज गर्ल की तरह अपने गर्ल गैंग को घर बुला कर पाजामा पार्टी कर सकती हैं, अपनी मरजी से ड्रैसअप हो सकती हैं, अपने पेरैंट्स, रिलेटिव्स को अपने घर अपने साथ रख सकती हैं. इस मेरी मरजी वाले टौनिक से आप ज्यादा खुश, रिलैक्स रहेंगी और यह सब जानते ही हैं कि एक खुश, संतुष्ट व्यक्ति ही औरों की दुनिया में खुशियां बिखेर सकता है.

3. फिट, यंग व खूबसूरत

आप अपने आप पर ज्यादा ध्यान देती हैं. आप का खयाल रखने वाला दूसरा कोई नहीं होने से अपनी डाइट, हैल्थ, ब्यूटी ऐंड बौडी केयर सब आप की जिम्मेदारी हो जाती है और आज कैरियर गर्ल के लिए फिट, ग्लैमरस व प्रेजैंटेबल बने रहना जरूरी भी है व फायदेमंद भी. इसीलिए सिंगल गर्ल अन्य के मुकाबले लंबे समय तक न सिर्फ यंग नजर आती है, बल्कि बौडी भी शेप में रखती है और प्रभावशाली व्यक्तित्व की मालकिन होती है.

4. पूरी तरह से इंडीपैंडैंट

किसी रिलेशनशिप में न होने का मतलब है कि आप को अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है. आप को पैंपर करने के लिए, डेली रूटीन को आसान बनाने के लिए किसी मर्द का कुशन न होने से आप की सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है. हालात का मुकाबला आप अन्य महिलाओं से बेहतर करती हैं. यह आत्मनिर्भरता आप का आत्मविश्वास भी बढ़ाती है.

5. हर चुनौती स्वीकारती हैं

सिंगलहुड आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है. दिनबदिन आप यह सीखती हैं कि स्ट्रैसफुल सिचुएशन में और अचानक आ पड़ी मुसीबत का सामना कैसे करना है. अलगअलग शख्सीयत, मिजाज वाले व्यक्तियों व कौंप्लैक्स पर्सनैलिटी वाले लोगों से आप को कैसे डील करना है, बिना उन के ईगो को ठेस पहुंचाए, यह आप बेहतर समझती हैं. और जबजब आप यह करने में कामयाब होती हैं तबतब आप अलौकिक खुशी और संतुष्टि पाती हैं.

6. ब्यूटी स्लीप भरपूर

आप के पास भरपूर मी टाइम होता है, जिस के लिए विवाहित महिलाएं तरसती हैं. आप अपने डेली रूटीन, स्लीपिंग रूटीन अपनी बौडी, वर्क और जरूरत के मुताबिक सैट कर सकती हैं, साथ ही पार्टनर का रुठनामनाना, बच्चों व ससुराल की चिंता भी आप के सिर पर नहीं होती है. इसी वजह से आप के लिए हर रोज प्रौपर, स्ट्रैसफ्री ब्यूटी स्लीप को प्राप्त करना आसान हो जाता है. रातभर की अच्छी नींद न सिर्फ आप की खूबसूरती, फिजिकलमैंटल हैल्थ के लिए बेहद आवश्यक होती है, बल्कि इस से आप का दिमाग भी सक्रिय होता है और आप की कार्यक्षमता, एकाग्रता, स्किल में इजाफा होता है.

7. खुद का लाइफस्टाइल

आप किसी और के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, इस वजह से आप के पास काफी समय, ऊर्जा और रिसोंसेज होते हैं कि आप हैल्दी रूटीन फौलो कर सकें. अपने लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, ऐक्सरसाइज शैड्यल में बदलाव ला सकती हैं और अपनी लाइफ को बोरिंग होने से बचा सकती हैं.

8. मनी रिलेटेड इश्यू कम

आज के वर्किंग कपल के बीच मेरा पैसा, तेरा पैसा यानी मनी को ले कर होने वाले वादविवाद काफी स्ट्रैस पैदा करते हैं. खासतौर पर पत्नियां अपने पैसे का क्या करती हैं या उन को क्या करना चाहिए, यह अकसर पति तय करते देखे जाते हैं. लेकिन सिंगल होने का मतलब है कि आप को अपनी मनी को कहां, किस तरह से खर्च करना है, किस पर करना है या कितनी सेव करनी है, इन सब बातों को ले कर किसी को जवाब नहीं देना है. आप का पैसा पूरी तरह आप का है. आप शौपिंग करें, स्पा जाएं या इन्वैस्ट करें, आप की मरजी. यही फाइनैंशियल इंडीपैंडैंस और फाइनैंशियल सिक्युरिटी आप को मजबूत बनाती है, आप का कौन्फिडैंस बढ़ाती है और सच्चे अर्थों में आप को मर्द के बराबर ला खड़ा करती है.

9. अलग पहचान बना सकती हैं

कैरियर में सैट होने के बाद अपनी हौबी को पुनर्जीवित कर सकती हैं, जो वक्त या पैसे की कमी के चलते अधूरी रह गई थी. जौब से लौटने के बाद बचे वक्त में थिएटर, स्क्रिप्ट राइटिंग, क्ले पेंटिंग या संगीत के प्रति अपने पैशन को नई दिशा दे सकती हैं. अपनी खुद की एक अलग पहचान बना सकती हैं. किसी भी तरह का रचनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी आप के दिलदिमाग को सुकून पहुंचाएगी.

10. जब चाहें हौलिडे पर जाएं

सिंगल होने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी मरजी, मूड और पसंद के मुताबिक हौलिडे प्लान कर सकती हैं. वह डैस्टिनेशन चुन सकती हैं जहां जाना आप की हमेशा ख्वाहिश रही है. पार्टनर की मरजी के हिसाब से कंप्रोमाइज करना, अपना मन मारना, जोकि अमूमन महिलाएं करती हैं, ये सब आप को नहीं करना पड़ेगा. चाहें तो बर्फीली पहाड़ियों की ऊंचीऊंची चोटियों को निहारें या फिर समंदर किनारे रेत पर नंगे पैर चलें, आप ताजा दम हो कर सकारात्मक ऊर्जा में सराबोर हो कर ही घर लौटेंगी.

फूलों से मिलेगी तरक्की को रफ्तार

तेजी से विकसित होते फूल उद्योग से जुड़ना चाहते हैं तो इस सेक्टर में आपके लिए अपना करियर संवारने के ढेर सारे मौके हैं। फूलों की खेती से जुड़ी कई तरह की जॉब करके आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं और अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं।

अगर आपने हॉर्टीकल्चर जैसे विषय के साथ एग्रीकल्चर में बीएससी किया हुआ है या चार साल की बीएससी (हॉर्टीकल्चर) की डिग्री ली है तो फ्लोरीकल्चर में मास्टर्स कर लेने पर प्रोफेशनल कामयाबी हासिल करने के आपके पास ढेरों मौके हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत में फ्लोरीकल्चर सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय के तौर पर उभरा है। वर्तमान में देश की लगभग 260 हजार एकड़ भूमि फ्लोरीकल्चर के लिए उपयोग में लाई जा रही है। एक अनुमान के अनुसार फूलों की वार्षिक घरेलू मांग 25 फीसदी से ऊपर है और इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार लगभग 90,000 करोड़ रुपये का है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भारतीय फूलों के मुख्य आयातकों में से हैं।

झारखंड और बिहार में गरबेरा और गुलाब की खेती लगभग 100 हेक्टेयर में की जाती है, वहीं गेंदे और दूसरे किस्म के फूलों की खेती 120 हेक्टेयर में की जाती है। हालांकि कई जिलों में फूलों की खेती की जाती है, लेकिन रांची, गुमला, सरायकेला, रामगढ़, देवघर और पूर्वी सिंहभूम जिले मुख्य रूप से फूलों की खेती के लिए जाने जाते हैं।

बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मौसम में ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। इन राज्यों में फूलों की खेती में अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो फूलों को मौसम की मार से बचाना जरूरी है। ग्रीन हाउस तापमान को प्राकृतिक रूप से 5-10 डिग्री तक कम कर देता है, लेकिन खुला होने की वजह से इसमें तामपमान पूरी तरह नियंत्रित नहीं होता। इसमें पॉली हाउस तकनीक कारगर साबित होती है, क्योंकि इसमें तापमान को पूरी तरह नियंत्रित करके ठंडा रखा जाता है, जिससे फूलों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता और पैदावार अच्छी होती है।

ये हैं किस्में

अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए मुख्य रूप से रोज, कारनेशन, क्राइसेंथेमम, गारगेरा, ग्लेडिओलस, जिप्सोफिला, लिएसट्रिस, नेरिन, ऑर्चिड, आर्चीलिया, एनथूरियू, ट्यूलिप और लिली जैसे फूलों का उत्पादन होता है। जहां गरबेरा और कारनेशन का उत्पादन अत्याधुनिक पॉली हाउस में किया जाता है, वहीं गुलाब, जैसमिन और ट्यूबरस आदि को ग्लास हाउस और शेड में रखा जाता है।

जॉब की अच्छी संभावनाएं

क्वालीफाइड फ्लोरीकल्चर स्पेशलिस्ट सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही सेक्टरों में अच्छी नौकरियां पा सकते हैं। हाइड्रोफोनिक्स, लैंडस्केप क्रिएशन, फूलों की सजावट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, माइक्रो प्रोपेगेशन, मार्र्केटिंग, फूलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिसर्च जैसे काम इस सेक्टर में किए जाते हैं, जिनमें फ्लोरीकल्चरिस्ट के लिए अलग-अलग तरह की जॉब्स होती हैं। आइए जानें कि किस तरह से इस सेक्टर में आपके लिए जॉब के क्या विकल्प उपलब्ध हैं-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

करियर काउंसलर यशोधरा अरोड़ा का कहना है, 'मौसमी व्यवसाय होने के कारण साल के कुछ ही महीने अच्छा बिजनेस मिलता है, जिसमें फायदा 80-90 फीसदी तक भी हो सकता है, लेकिन सीजन जाने के बाद यह भी मुमकिन है कि मुनाफा बिल्कुल न हो। इस सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी स्किल्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। फूलों की तमाम किस्मों, उनके लिए अनुकूल तापमान, उनकी प्रकृति और पैदावार आदि के बारे में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए।'

सौदामिनी पांडेय

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड जगदलपुर (छग)
Office Phone No. 07782-222224, 223443 Email ID-eejag-phe-cg@nic-in

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना (प्रथम आमंत्रण)

नि.क्र/ ज.जी.मि.-460/नि.प्र./का.अ./लो.स्वा.यॉ.ख./2024 जगदलपुर, दिनांक 13.03..2024

1. एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रपत्र सी में आयटम दर पर बस्तर जिले के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल ग्राम/रेट्रोफिटिंग ग्राम हेतु Wall Writing with Painting कार्य हेतु आनलाईन (Online) रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है-

निविदा सूचना क्रमांक	सिस्टम निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.लाख में)
460/13.03.2024	154160	The Executive Engineer and Member Secretary DWSM District Bastar invites Expression of Interest (EoI) from the registered firms having experience in the similar nature of works, for fixation of rate contract for Wall Writing with Painting proposed under Jal Jeevan Mission to be implemented by District Water and Sanitation Mission (DWSM), Chhattisgarh..	16.60

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा दिनांक 04.04.2024 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https:\\eproc.cgstate.gov.in पर दर्शित एवं डाउनलोड की जा सकती है ।

कार्यपालन अभियंता
जी- 08555/3 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, जगदलपुर (छग)

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

लोकसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। ईसीआई ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की भी घोषणा करेगा। सूत्रों के अनुसार आम चुनाव 2024 और कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, 16 मार्च को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसे ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव सात से आठ चरणों में होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को यहां कहा कि निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ या अलग-अलग कराने पर फैसला करेगा।

सीएए पर रोक की मांग, 19 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया जिन्होंने कहा कि मामला अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाएगा। 2019 से शीर्ष अदालत में दायर दो सौ से अधिक संबंधित याचिकाओं में विभिन्न सीएए प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इस कानून का उद्देश्य गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे। सीएए को दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने सोमवार को इसके लिए नियम जारी किए।

नए निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश और सुखबीर ने संभाला प्रभार

नयी दिल्ली। नव नियुक्त निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने शुक्रवार को अपना प्रभार संभाल लिया। दोनों पूर्व नौकरशाहों को बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में हाल में एक नया कानून लागू होने के बाद, निर्वाचन आयोग में नियुक्त किए गए पहले सदस्य हैं। एक प्रवक्ता ने बताया कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने ऐसे ऐतिहासिक समय पर उनकी नियुक्ति के महत्व के बारे में बात की जब निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव कराने की तैयारियां कर रहा है। अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और आठ मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में ये पद खाली हो गए थे। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों वर्ष 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं।

पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका राज कुमार आप में हुए शामिल

चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक झटका लगा है क्योंकि पंजाब से पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक राज कुमार चब्बेवाल ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ दी और राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। चब्बेवाल (54) ने कहा कि उन्होंने होशियारपुर जिले के चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक के तौर पर भी इस्तीफा दे दिया है। प्रमुख दलित नेता चब्बेवाल पंजाब विधानसभा में विपक्ष के उपनेता थे। वह यहां आप में शामिल हुए और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका पार्टी में स्वागत किया। चब्बेवाल एक सप्ताह के भीतर आप में शामिल होने वाले पंजाब से कांग्रेस के दूसरे नेता हैं। बस्सी पठाना से कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी हाल ही में आप में शामिल हुए थे। आप की प्रदेश इकाई ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि चब्बेवाल के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई है। आप ने मान द्वारा चब्बेवाल के स्वागत की तस्वीरों को भी पोस्ट किया।

उत्तरप्रदेश में भाजपा को झटका श्याम किशोर बसपा में शामिल

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी निवासी अवध क्षेत्र की कार्य समिति के सदस्य श्याम किशोर अवस्थी ने भाजपा से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, बसपा धौरहरा से उन्हें प्रत्याशी घोषित कर सकती है। दरअसल, बसपा को इस सीट के लिए ब्राह्मण चेहरे की ही तलाश है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह को भेजे त्यागपत्र में श्याम किशोर अवस्थी ने बताया है कि वह स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों और जिम्मेदारियों का त्याग कर रहे हैं। त्यागपत्र भेजे जाने की सूचना मिलने के बाद भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि वह एक सांसद के करीबी थे, लेकिन अनबन होने के बाद उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और बसपा की सदस्यता ले ली है। बसपा जिलाध्यक्ष हेमराज वर्मा ने कहा कि श्यामकिशोर का बसपा में स्वागत है। उधर, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह का कहना है कि उन्हें इस्तीफे की जानकारी नहीं है।

कन्याकुमारी में लगे मोदी मोदी के नारे, पीएम बोले दिल्लीवालों की नींद खराब हो जाएगी

कांग्रेस गठबंधन राज्य का कभी विकास नहीं कर सकता

चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (15 मार्च) को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। जनसभा के दौरान महिला बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने कहा, तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक का अहंकार टूट जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के लोग जम्मू-कश्मीर के निवासियों की तरह देश को तोड़ने का सपना देखने वाले लोगों को अस्वीकार कर देंगे। पीएम मोदी ने कहा आज देश के दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी से जो लहर उठ रही है, वह बहुत दूर तक जाएगी। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना देखने वाले लोगों को खारिज कर दिया। अब, तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं।

पीएम मोदी ने डीएमके-कांग्रेस गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि वे राज्य का विकास नहीं कर सकते क्योंकि उनका इतिहास घोटालों से भरा है। उन्होंने कहा, डीएमके तमिलनाडु की दुश्मन है। डीएमके-कांग्रेस का आईएनडीआई गठबंधन कभी भी तमिलनाडु को विकसित राज्य नहीं बना सकता क्योंकि इसका इतिहास घोटालों और भ्रष्टाचार का है।

तमिलनाडु में एक सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को खारिज कर दिया, तमिलनाडु भी ऐसा ही करेगा। लोगों को लूटने के लिए द्रमुक और कांग्रेस सत्ता में आना चाहती हैं, 2जी घोटाले में द्रमुक को सर्वाधिक लाभ मिला। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की ओर विकास की पहल है, 'इंडिया' गठबंधन की तरफ घोटाले हैं : प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के विभिन्न घोटाले गिनाते हुए कहा कि सूची बहुत लंबी है।

कन्याकुमारी की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिले के लिए की गई विभिन्न पहलों पर नजर रखे हुए है केंद्र। तमिलनाडु के भविष्य, उसकी संस्कृति की दुश्मन है द्रमुक, अयोध्या मंदिर कार्यक्रम का प्रसारण 'प्रतिबंधित किया। द्रमुक को देश, इसकी संस्कृति और विरासत से नफरत है। द्रमुक तमिलनाडु का दुश्मन, कांग्रेस गठबंधन कभी भी राज्य का विकास नहीं कर सकता।

इंडी अलायंस के ये लोग तमिलनाडु के लोगों की

जिंदगियों से खिलवाड़ के भी जिम्मेदार हैं। श्रीलंका में हमारे मछुआरे भाइयों को फांसी की सजा दी गई थी, ये मोदी चुप नहीं बैठा। हर रास्ते का इस्तेमाल किया और हर प्रकार का दबाव बनाया और मैं उन सभी मछुआरों को श्रीलंका से फांसी के फंदे से उतारकर वापस लाया।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि मुझे तकलीफ है कि मुझे तमिल नहीं आती। लेकिन, तमिल भाषा के प्रति मेरा प्यार बहुत ज्यादा है। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि क्या आप सभी लोग मेरी मन की बात तमिल में सुनेंगे। पीएम के सवाल का जवाब देते हुए सभा में मौजूद जनता ने कहा कि हां मोदी जी।

पीएम मोदी ने कहा कि जब दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी तो तमिल संस्कृति के प्रतीक, इस धरती के आशीर्वाद स्वरुप पवित्र सेंगोल को हमने नए भवन में स्थापित किया। लेकिन इन लोगों ने इसका भी बॉयकॉट किया, उन्हें सेंगोल की स्थापना पसंद नहीं आई। डीएमके और कांग्रेस तब भी चुप बैठी रही, जब जल्लीकट्टू पर पाबंदी लगी थी। ये लोग तमिल संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है जिसने जल्लीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का गौरव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डीएमके तमिलनाडु के भविष्य की ही दुश्मन नहीं है।

डीएमके तमिलनाडु के अतीत की, उसकी विरासत की भी दुश्मन है। मैं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यहां आया था, मैंने यहां के प्राचीन तीर्थों के दर्शन किए थे। लेकिन डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी।

पीएम ने कहा कि हम तमिलनाडु के बंदरगाह बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने हाल ही में थूथुकुडी में चिदंबरनार बंदरगाह का उद्घाटन किया है। हमारी सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। उन्हें आधुनिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाने तक, हमने उनकी जरूरतों का ख्याल रखा है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के विकास पर भी बात की। उन्होंने बताया कि राज्य में कनेक्टिविटी को विकसित करने के लिए वह रेलवे और हाईवे का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का काम पूरा हो चुका है। वहीं 70,000 करोड़ रुपये की परियोजना का काम अभी भी जारी है।

केरल में भ्रष्ट और नाकाबिल सरकार: मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी केरल के पथानामथिट्टा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। सार्वजनिक रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पथनमथिट्टा का माहौल बात रहा है कि इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसलिए केरल के लोग कह रहे है कि अबकी बार 400 पार। पिछले चुनाव में केरल की जनता ने हमें दोहरे अंक में वोट प्रतिशत वाली पार्टी बनाया. और अब, यहाँ दोहरे अंक वाली सीटों की हमारी नियति अभी दूर नहीं है! पीएम मोदी ने कहा कि केरल के लोग राज्य पर शासन करने वाली भ्रष्ट और अक्षम सरकारों के कारण पीड़ित हैं। एलडीएफ और यूडीएफ सरकारें रबर किसानों की दुर्दशा पर अंधी हो गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केरल में कानून व्यवस्था भी बेहद खराब स्थिति में है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल में चर्च के पुजारी भी सुरक्षित नहीं हैं। कानून-व्यवस्था की शर्मनाक स्थिति के कारण वे हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, असंख्य कॉलेज कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन गये हैं।

कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर उठाए सवाल

भाजपा करोड़ों रुपये का चंदा लिया पर हमारे खाते सीज कर दिए: खड़गे

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। कांग्रेस ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एंट्री में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड से पैसे बनाए हैं और उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की। खरगे ने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते आयकर विभाग ने सीज कर दिए हैं, इससे चुनाव में बराबरी की लड़ाई कैसे होगी?

बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा और न खाने दूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका पर्दाफाश कर दिया है कि किस तरह से भाजपा ने चुनावी बॉन्ड से पैसे बनाए। खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। उन्होंने (भाजपा) आयकर विभाग को ऐसा करने का निर्देश दिया। हमारे करीब 300 करोड़ रुपये जब्त हैं। ऐसे में हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? हमारे खाते बंद है और उनके खुले हुए हैं। ऐसे में बराबरी का मुकाबला कैसे होगा? हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जब तक सच बाहर न आए, तब तक उनके खाते भी सीज होने चाहिए। खरगे ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की 50 प्रतिशत से ज्यादा रकम सिर्फ भाजपा को मिलने पर गंभीर सवाल उठाए और इसकी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सच बाहर आना चाहिए। क्या चंदे के बदले कोई लाभ पहुंचाया गया।

कांग्रेस के संचार विभाग के रिसर्च और मॉनिटरिंग शाखा के प्रभारी अमिताभ दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में कांग्रेस नेता लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना साल 2017 में शुरू की गई थी, लेकिन जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वह अप्रैल 2019 से हैं। आंकड़ों में

दानदाताओं की 18,871 एंट्री है, वहीं दान लेने वालों की एंट्री की संख्या 20,421 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग ये अनियमितता क्यों है? अमिताभ दुबे की इस पोस्ट को कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने भी रि-पोस्ट किया है और एंट्री की गड़बड़ी पर सवाल उठाए। मणिकम टैगोर ने पोस्ट में लिखा कि मुझे नहीं लगता कि ये एक संयोग है।

चुनाव आयोग द्वारा जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, उनमें बॉन्ड खरीदने वाले और इन बॉन्ड को भुनाने वालों के तो नाम हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता कि किसने यह पैसा किस पार्टी को दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ याचिका दायर करने वाले एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने भी इस बात को उठाया है। इस मुद्दे को लेकर एडीआर फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।

चुनाव आयोग ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। जो आंकड़ा सार्वजनिक किया गया है, उसमें 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का डाटा है। भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा 6,060 करोड़ रुपये का चंदा मिला। भाजपा के बाद टीएमसी को 1609 करोड़ रुपये, कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपये, बीआरएस को 1214 करोड़ रुपये, बीजद को 775 करोड़ रुपये और डीएमके को 639 करोड़ रुपये का चंदा मिला।

खेल
प्रमुख समाचार

आल इंग्लैंड चैम्पियनशिप से बाहर सात्विक-चिराग की जोड़ी

नईदिल्ली। भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी

और चिराग शेट्टी की दुनिया की नंबर एक जोड़ी गुरुवार रात यहां आल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के पुरुष युगल प्री क्वार्टरफाइनल से बाहर हो गयी।

भारतीय जोड़ी को प्री क्वार्टरफाइनल में इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिल फिकरी और बागास मौलाना की जोड़ी से 16-21 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। इंडोनेशियाई जोड़ी यहां 2022 में चैम्पियन रही थी।

शीर्ष वरीय भारतीय जोड़ी ने पिछले हफ्ते फ्रेंच ओपन खिताब जीता था लेकिन यहां तीसरी वरीयता प्राप्त प्रतिद्वंद्वियों के दबाव से नहीं निपट सकी और एक घंटे से ज्यादा समय तक चले मुकाबले में हारकर बाहर हो गयी।

तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी भी महिला युगल के राउंड 16 से बाहर हो गयी। उन्हें चीन की झांग शु जियान और जेंग यु से 21-11 11-21 11-21 से पराजय झेलनी पड़ी।

शुक्रवार को भारत के लक्ष्य सेन का सामना पुरुष एकल क्वार्टरफाइनल में मलेशिया के ली जि जिया से होगा। लक्ष्य ने दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन पर 24-22 11-21 21-14 की जीत से क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। लेकिन दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू का अभियान दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की एन से यंग से 19-21 11-21 से हारकर समाप्त हो गया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 450 अंक फिसला तो निफ्टी 22 हजार के नीचे बंद

नईदिल्ली। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई जिससे बीएसई सेंसेक्स लगभग 1 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज पिछले बंद भाव के मुकाबले गिरावट के साथ 72,886 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 72,484.82 अंक के निचले स्तर तक चला गया था। अंत में सेंसेक्स 0.62 प्रतिशत या 453.85 अंक की गिरावट लेकर 72,643.43 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तीस कंपनियों में से 24 के शेयर लाल जबकि केवल 6 कंपनियों के शेयर ग्रीन निशान में बंद हुए। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 0.68 फीसदी या 150.10 अंक की गिरावट के साथ 22 हजार के स्तर से नीचे आते हुए 21,996.55 अंक पर क्लोज हुआ।

'मेन्युफेक्चरिंग हब' बनाने के लिए ईवी पॉलिसी का ऐलान

नईदिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को भारत को 'मेन्युफेक्ररिंग हब' के रूप में बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत भारत को ईवी के मेन्युफेक्ररिंग डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने और प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। नीति के तहत किसी कंपनी को कम से कम 50 करोड़ डॉलर (4,150 करोड़ रुपये) का निवेश करना जरूरी होगा। योजना के तहत विभिन्न शुल्क रियायत भी दी जाएंगी। मंत्रालय ने कहा, यह भारतीय उपभोक्ताओं को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करेगा, 'मेक इन इंडिया' (भारत में उत्पादन करो) पहल को बढ़ावा देगा, ईवी कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर ईवी के माहौल को मजबूत करेगा।

पेटीएम से यूपीआई ट्रांजैक्शन जारी रखने मिले 5 हैंडल

नईदिल्ली। पेटीएम को डिजिटल पेमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से थर्ड-पार्टी ऐप लाइसेंस मिल गया है। रिजर्व बैंक के आदेश पर पेटीएम की बैंकिंग युनिट बंद होने के बाद पेटीएम यूजर्स के लिए यह राहत भरी खबर है। इससे पेटीएम की मुश्किलें कुछ कम हो जाएंगी। पेटीएम यूजर्स को यह लाइसेंस यूपीआई के माध्यम से भुगतान के लिए पेटीएम ऐप का उपयोग जारी रखने की अनुमति देगा। मालूम हो कि कुछ मानकों का अनुपालन न करने के कारण पेटीएम की बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 15 मार्च से परिचालन बंद करने को कह दिया गया है। वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस को यूपीआई लेनदेन जारी रखने के लिए चार बैंकों के साथ साझेदारी में पांच हैंडल मिले हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यह जानकारी दी है।

सरकार ने घटाया दाम तो तेल कंपनियों को लगा झटका

नईदिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी तेल बाजार कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को गिरावट आई। बीएसई पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का शेयर 8.10 प्रतिशत का गोता लगा कर 459.60 रुपये पर आ गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर 6.80 प्रतिशत गिरकर 158.40 रुपये पर और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर 6.37 प्रतिशत गिरकर 570.20 रुपये पर आ गए। कीमतों में बदलाव के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल अब 94.72 रुपये प्रति लीटर हो गया, जो पहले 96.72 रुपये प्रति लीटर था, जबकि डीजल की कीमत अब 87.62 रुपये हो गई, जो पहले 89.62 रुपये थी।

दवा कंपनियों से उपहार या आर्थिक लाभ लेने पर पाबंदी

डॉ. ईश्वर गिलाडा

भारत सरकार ने दवा कंपनियों द्वारा चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों या उनके परिवारों को व्यक्तिगत लाभ मुहैया कराने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए संहिता जारी की है। इस संहिता- यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी) 2024- के तहत इस नियमन को लागू करने की जिम्मेदारी कंपनियों की होगी। अपने उत्पादों को बेचने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को उपहार, यात्रा सुविधा, हॉस्पिटैलिटी, नगदी आदि देने की शिकायतों के निपटारे के लिए फार्मा कंपनियों को एक एथिक्स कमिटी बनानी होगी, जिसमें तीन से पांच सदस्य होंगे। इस समिति के प्रमुख बोर्ड के सीइओ होंगे। इस कमिटी की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी। कोड में स्पष्ट कहा गया है कि नियमन के पालन के लिए कंपनी के सीइओ जिम्मेदार होंगे। उन्हें हर वित्त वर्ष की समाप्ति के दो माह के भीतर यह घोषणा देनी होगी कि उनकी कंपनी नियमों का पालन कर रही है और उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को किसी भी तरह का व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जा रहा है। कोड में ऐसे किसी व्यक्ति को मुफ्त सैंपल दवा देने की भी मनाही है, जो ऐसे किसी उत्पाद को मरीजों को देने के लिए योग्य नहीं है। जो सैंपल दवा डॉक्टरों को दिये जाते हैं, उनका मूल्य कंपनी के कुल घरेलू बिक्री के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछली बार फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा नियमन 2014 में लाया था।

ऐसा नियमन इसलिए करना पड़ा है क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियां डॉक्टरों को विदेश यात्रा पर ले जाती हैं। ऐसा भी होता है कि

कंपनियां स्वास्थ्यकर्मियों के निजी उत्सवों, मसलन जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ आदि, का खर्च उठाती हैं। महंगे उपहार भी दिये जाते हैं। इसके बदले में वे कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाना चाहती हैं। यह एक तरह का लेन-देन है कि हम आप पर खर्च कर रहे हैं और आप हमारे उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में मदद करें। कोई भी कंपनी अपने उत्पाद के प्रचार-प्रसार के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम और उपाय करती है। वैसा ही माहौल मेडिकल पेशे में भी आ गया। इस पेशे में अपनी जानकारी को समय-समय पर बढ़ाना तथा दूसरे चिकित्सकों के अनुभवों से सीख लेना जरूरी होता है। इसके लिए सम्मेलन, वर्कशॉप और सेमिनार होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि ऐसे आयोजनों से अपनी जानकारी बढ़ाकर हम अपने मरीजों को बेहतर उपचार मुहैया करायें। हर डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल में अपने पंजीकरण का हर पांच साल में नवीनीकरण कराना होता है और उसके लिए 30 क्रेडिट प्वाइंट का विवरण जमा करना होता है। इसके लिए कम से कम 120 घंटे के शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेना होता है। किसी भी अन्य पेशे में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती।

अगर यह बाध्यता चिकित्सकों के लिए सरकार की तरफ से निर्धारित है, तो ऐसे कार्यक्रम भी सरकार, मेडिकल काउंसिल और विश्वविद्यालयों की ओर से आयोजित किये जाने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक एसोसिएशनों को अपने स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम करने पड़ते हैं और जहां खर्च करने की बात आती है, तो दवा कंपनियां खर्च करती हैं क्योंकि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों से लाभ होता है। लेकिन इस संबंध में नियम यह स्थापित किया गया है कि प्रायोजक कंपनियों के उत्पादों को मुख्य सम्मेलन कक्ष में प्रदर्शित नहीं किया जाता है और न ही उसके उत्पादों के नाम के साथ आयोजन का प्रचार होता है। अब होता यह है कि गलत करने वाले लोगों के कारण सही करने वालों पर भी आंच आती है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों को नहीं रोका जाना चाहिए या फिर सरकार को उसके लिए वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। ऐसा नहीं होने से कंपनियों और डॉक्टरों का एक गलत गठजोड़ बनेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी गड़बड़ियां हैं, उन्हें दूर करने के लगातार प्रयास होने चाहिए। इस संदर्भ में भारत सरकार का नया नियम एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लेकर प्रदेश सरकार ने मोदी की एक और गारंटी पूरी की : भाजपा

प्रदेश अध्यक्ष देव ने कर्मचारियों के मुद्दे हल करने समिति गठित करने और भत्ता बढ़ाने के फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का किया आभार और कर्मचारियों को बधाई दी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अस्थायी, संविदा आदि कर्मचारियों के मसलों पर विचार कर उनकी दिक्कतों के ठोस परिमार्जन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा एक समिति का गठन किए जाने का स्वागत कर बधाई दिया है। श्री देव ने कहा कि भाजपा सरकार ने यह समिति गठित करके 'मोदी की गारंटी' पूरी करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक फैसला करके साबित किया है कि भाजपा जो कहती है, वह पूरा करके दिखाती है। प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि मोदी गारंटी से संबंधित एक और निर्णय डीए बढ़ाने का है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में

एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कर्मचारियों के हित में लिए फैसलों के लिए प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि मोदी की गारंटी में भाजपा ने जो घोषणा की थी, उनमें से एक और घोषणा को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार अपने 100 दिनों के अत्यल्प कार्यकाल में ही बड़े-बड़े वादों को पूरा कर दिया है और आने वाले समय में दिए गए समस्त वादों को भाजपा की सरकार पूरा करेगी। श्री देव ने कहा कि ने कहा कि प्रदेश सरकार के फैसलों के दृष्टिगत पूरा छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास करने लगा है और यह मान रहा है कि मोदी की गारंटी स्वयं में गारंटी पूरी होने की गारंटी है। किरण देव ने कहा कि पंचायत सचिवों को नियमित करेंगे एवं उनका बकाया एरियर पी.पी.एफ. में जोड़े जाने का निर्णय भी ऐतिहासिक है। प्रदेश सरकार ने अपने संकल्पों की पूर्ति की दिशा में कदम उठाकर प्रदेश में विश्वास का संचार किया है। श्री देव ने कहा कि भाजपा सरकार जन-सेवा का एक संकल्प लेकर काम कर रही है।

समाज और मानवता के लाभ के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें - राज्यपाल हरिचंदन

रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज एमिटी विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज व समग्र मानवता के लाभ के लिए अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने हेतु संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब व वंचित लोगों के लिए विद्यार्थियो को काम करना है। पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्री हरिचंदन ने 22 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 16 को रजत पदक और 5 को कांस्य पदक प्रदान किए। समारोह में वर्ष 2023 बैच के 681 विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां वितरित की गईं। विश्वविद्यालय द्वारा डीएआरई के सचिव और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई ।

बच्चियों और महिलाओं पर बढ़ते अपराध रोकने में भाजपा सरकार नाकाम

आदिवासी 8 बच्चियों के साथ शारीरिक एवं मानसिक शोषण नारायणपुर जिले की घटना से छत्तीसगढ़ महतारी की आंखें शर्म से झुक गई

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में बच्चियों के साथ हो रहे अपराध को

रोकने में बीजेपी सरकार नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चियों और महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार की बढ़ती घटना ने भाजपा की सरकार की कलाई खोल दी है। नारायणपुर जिले की हृदय विदारक घटना से छत्तीसगढ़ महतारी के शर्म से आंखें झुक गई है। नाबालिक 8 आदिवासी बच्चियों के साथ विद्या के मंदिर में शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा था जिसकी जानकारी प्रशासन को भी रहने के बावजूद हाथ में हाथ लिए तमाशा देख रहे थे और पीड़ित परिवार को ही माफीनामा लिखवाने में लगे हुए थे। माता-पिता अपने बच्चों को लेकर के चिंतित, भयभीत है। शासन प्रशासन के उदासीनता के कारण आरोपी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं। बेटी बचाओ के नारा लगाने वाले अपने आंखें खोल कर देखो भाजपा की सरकार में नाबालिक बच्चियों के साथ अत्याचार, अनाचार और बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आज बच्चियां स्कूल जाने के नाम से डर रही है ऐसे में कैसे बेटी को बचाएंगे और बेटी को पढ़ाएंगे।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि डबल इंजन वाली भाजपा की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अनाचार बढ़ रही है। राजिम में एक 10 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ, इसी हफ्ते बालोद जिले में 2 वर्षीय बच्ची के साथ, अंबिकापुर जिले में नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटती है। दुर्ग में एक नाबालिक बच्ची को दिनदहाड़े जान से मारने के लिए धारदार हथियार से वार किया जाता है। अनेक ऐसी घटनाएं घटती है। बहुत सारी घटनाओं का तो थाने में अपराध दर्ज भी नहीं किया जा रहा है। डबल इंजन के सरकार में अंकुश लगाने में नहीं बल्कि घटनाओं प्रतिक्रियाओं को रोकने और दबाने में लगी रहती है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा के महिला नेत्रियां क्या अवसरवादी राजनीति करती है? नारायणपुर जिले की घटना में एक भी भाजपा नेत्रियां जाकर के उस पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलती है? प्रदेश के मुखिया आदिवासी है लेकिन हमारे आदिवासी बच्चियां सुरक्षित नहीं है क्यों?

खैरागढ़ उप चुनाव में हुआ कोयला घोटाले के पैसे का उपयोग: ईडी

रायपर। प्रदेश के बहुचर्चित कोल घोटाले के मुख्य आरोपित सूर्यकांत तिवारी और भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव की घोटाले में संलिप्तता का ईडी ने हाई कोर्ट में राजफास किया है। खैरागढ़ उप चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधायक देवेन्द्र यादव को चुनाव संचालन की जिम्मेदारी दी थी। विधायक यादव ने सूर्यकांत तिवारी को फोन कर खैरागढ़ में कार्यक्रम कराने पैसे की मांग की। इस पर पूर्व मंत्री मो अकबर के बंगले के सामने नवाज नामक व्यक्ति ने 35 लाख रुपये देवेन्द्र यादव को दी.ईडी ने कोल घोटाले में विधायक यादव की संलिप्तता बताते हुए अग्रिम जमानत देने का विरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को इस बात की भी जानकारी दी है कि विधायक यादव को सूर्यकांत तिवारी ने तीन करोड़ का भुगतान किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस व्यास ने विधायक यादव की अग्रिम जमानत याचिका को

खारिज कर दिया है। आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत एक तलाशी और जब्ती जांच के दौरान 30.जून.2022 को बेंगलुरु के होटल शेरेटन ग्रैंड के कमरे में सूर्यकांत तिवारी के पास कुछ आपत्तिजनक सामग्रियां मिली थीं। जिसके आधार पर आयकर विभाग द्वारा कडुगोडी, पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में आइपीसी की धारा 120 बी, 186, 204 और 353 के तहत एफआइआर दर्ज की गई। जांच के दौरान मुख्य आरोपित सूर्यकांत तिवारी को 13.अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने हाई कोर्ट में पेश दस्तावेज में बताया है कि सूर्यकांत तिवारी ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें नष्ट कर दिया। सूर्यकांत तिवारी ने अपने भाई, रजनीकांत तिवारी और उनके सहयोगियों हेमंत जयसवाल, जोगेंद्र सिंह, मोइनुद्दीन कुरैशी, निखिल चंद्राकर, रोशन के साथ मिलकर काम किया। जोगेंद्र सिंह और अन्य लोग कोयले पर अवैध लेवी वसूलने की समानांतर प्रणाली चलाने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल थे और सूर्यकांत के निर्देशानुसार अवैध और बेहिसाब नकदी की आवाजाही कर रहे थे। सूर्यकांत तिवारी के उपरोक्त सभी सहयोगियों ने आयकर अधिकारियों के समक्ष दर्ज कराये गये अपने बयान में स्वीकार किया था कि वे सूर्यकांत तिवारी के निर्देश पर अवैध लेवी वसूली कर रहे थे. उपरोक्त संदर्भित कार्रवाई से प्राप्त आय का उपयोग अनुचित लाभ लेने और भ्रष्ट और अवैध तरीकों और व्यक्तिगत प्रभाव के प्रयोग से लोक सेवकों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था। ईडी ने विधायक यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि सूर्यकांत तिवारी से तीन करोड़ रुपये लिए। विधायक यादव ने अपने बयान में पुष्टि की है कि सूर्यकांत तिवारी उन्हें पांच साल से जानते हैं। वह सूर्यकांत तिवारी के साथ फोन व वाट्सएप काल पर बातचीत करते थे और अप्रैल, 2022 में आयोजित खैरागढ़ उपचुनाव के प्रभारी होने के नाते, वह चुनाव प्रचार, खैरागढ़ उपचुनाव से संबंधित पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रबंधन आदि की देखभाल कर रहे थे।

निखिल के बयान और वाट्सएप ग्रुप से हुआ राजफाश- ईडी ने धारा 17 के तहत निखिल चंद्राकर का बयान दर्ज किया है। डायरी के एक पन्ने में नौ अप्रैल 2002 को खैरागढ़ उपचुनाव के लिए विधायक यादव द्वारा सूर्यकांत तिवारी से 35 लाख रुपये प्राप्त करने का उल्लेख है। निखिल चंद्राकर ने 'दुर्ग ग्रुप' नामक वाट्सएप ग्रुप में हुई वाट्सएप चैट के साथ देवेंद्र यादव के नाम पर की गई नकद प्रविष्टियों की पुष्टि की है। जिसमें रजनीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर और रोशन सिंह सदस्य हैं.। निखिल ने ईडी को यह भी बताया है कि संबंधित व्यक्ति को राशि सौंपने के बाद, वे वास्तविक समय अपडेट के लिए वाट्सएप पर एक संदेश पोस्ट करता था। संदेश के बाद रजनीकांत तिवारी इसे अपनी हस्तलिखित डायरी में नोट कर लेते थे।

लेवी के बिना नहीं होता था पास जारी- ईडी ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि जब तक कोयला परिवहन के एवज में प्रति टन 25 रुपये का भुगतान सूर्यकांत तिवारी को नहीं किया जाता था तब तक छत्तीसगढ़ के संबंधित खनन अधिकारी, कलेक्टरेट कार्यालय से अपेक्षित पारगमन पास जारी नहीं किया जाता था। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी व छग शासन में पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया के प्रभाव से सूर्यकांत तिवारी द्वारा संगठित अपराध को संचालित किया जा रहा था। कोयले पर प्रति टन 25 रुपये लेते थे और लेवी वसूलने के बाद वसूली तिथि के साथ नकद राशि सूर्यकांत के घर पर रजनीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर और रोशन कुमार सिंह को सौंप देते थे।

मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, दिव्यांगजनों के लिए रैम्प आदि सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

रायपुर। नगर निगम आयुक्त एवं नोडल अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा ने आज लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर शहरी क्षेत्र में चल रही तैयारियों की समीक्षा की। श्री मिश्रा ने नगर निगम के सभी जोन कमिश्नरों और अन्य संबंधित सहायक नोडल अधिकारियों के साथ सभाकक्ष में बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। श्री मिश्रा ने मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों से लेकर इंडोर स्टेडियम, शुभाष स्टेडियम, सामुदायिक भवनों, टाउन हॉल, ऑडिटोरियम, स्वीमिंग पुल, लाइब्रेरी जैसी शासकीय परिसरों से भी सभी प्रकार की संपत्ति विरूपित करने वाले साधनों को समय-सीमा में हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मिश्रा ने कहा कि यदि कोई संपत्ति विरूपित करता है तो तत्काल निर्धारित समय-सीमा में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने व विरूपण हटाने की कार्यवाही करें।

पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न के लिए जांच कमेटी की घोषणा करने पर भाजपा मीडिया विभाग ने किया मुख्यमंत्री का आभार

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा पत्रकारों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मुकदमे एवं उत्पीड़न की जांच के लिए गृह सचिव के अध्यक्षता में कमेटी की घोषणा करने पर भाजपा मीडिया विभाग ने मुख्यमंत्री का आभार जताया हैं विगत दिनों भाजपा मीडिया विभाग की तरफ से ऐसे मामलों पर जांच करने की मांग की गई थी। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का यह कदम पत्रकार जगत के साथियों के प्रति मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का एक बड़ा प्रमाण है। पिछले 5 वर्षों के कांग्रेस शासन में अनेक अनेक पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर ,उनके साथ अत्याचार कर उनका उत्पीड़न किया गया ,मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा उनके साथ न्याय करने की एक बड़ी पहल है। भाजपा हमेशा पत्रकार जगत के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ती आई है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

परिवार को बंधक बनाकर डकैती, लाखों के कैश और जेवरात लेकर हुए फरार

रायपुर। राजधानी रायपुर में डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया है. माना बस्ती इलाके में 4 नकाबपोश बदमाशों ने देर रात घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों की डकैती की है. बताया जा रहा है कि लूटेरे घर में रखें लाखों के जेवरात नगदी समेत 10 लाख रुपये का सामान लेकर फरार हो गए. वहीं नकाबपोश बदमाशों ने घर के सदस्यों का हाथ-पैर बांधकर मारपीट भी की है. आरोपियों ने मास्टर-की से अलमारी का लॉकर खोला और घर के कीमती सामान ले उड़े. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समेत डॉग स्कॉड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच गई है. इस वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के मध्यप्रदेश के पत्थर गैंग के होने की आशंका है. जानकारी के मुताबिक, माना थाना क्षेत्र अंतर्गत माना बस्ती में गुरुवार की रात 3 से 4 बजे के बीच नकाबपोश 4 बदमाश कटर से एक घर का दरवाजा काटकर अंदर घुसे. जिसके बाद घर के सदस्यों को अलग-अलग कमरे में बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया.

आइपीएस अमरेश मिश्रा और राहुल भगत आईजी के लिए इम्पैनलमेंट हुए

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ कैडर के 2005 बैच के 2 आइपीएस अफसर का इम्पैनलमेंट करते हुए उन्हें आईजी पद पर पदोन्नत किया है। सूची में कुल 47 आइपीएस अफसरों को इम्पैनलमेट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आदेश आज जारी कर दिया गया है. इसके मुताबिक रायपुर के आईजी आइपीएस अमरेश मिश्रा को आईजी पद पर इमपैनलमेंट किया गया है, वे रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हैं। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अंवेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इसी तरह आइपीएस राहुल भगत को भी आईजी पद पर इमपैनलमेंट किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राहुल भगत सीएम सचिवालय के सचिव हैं तथा नए विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय

रायपुर। जमीन की खरीदी और बिक्री के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति और लोगों को सुविधाएं देने के लिए महानिरीक्षक पंजीयक ने मार्च महीने में पडऩे वाले 11 अवकाश के दिन होने के मद्देनजर आगामी 16 मार्च से शासकीय अवकाश शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खोलने और पंजीयन करने के आदेश जारी किए हैं। जमीन की खरीदी और बिक्री के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति और लोगों को सुविधाएं देने के लिए महानिरीक्षक पंजीयक ने मार्च महीने में पडऩे वाले 11 अवकाश के दिन होने के मद्देनजर आगामी 16 मार्च से शासकीय अवकाश शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खोलने और पंजीयन करने के आदेश जारी किए हैं। यानि 16 मार्च से 31 मार्च तक कुल आधादर्जन दिनों में भी पंजीयन कार्यालय में काम होंगे। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के माध्यम से, दस्तावेजों का पंजीयन, भारतीय स्टाम्प अधिनियम एवं पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के तहत करते हुए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क के रूप में, राज्य शासन के लिए राजस्व अर्जन करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम माह पूर्ण होनें में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें से शासकीय अवकाश के 11 दिन भी शामिल है। अवकाश के दिवस में पंजीयन कार्यालय बंद रहने से दस्तावेजों का पंजीयन प्रभावित होगा.

लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं ले जा सकेंगे 50 हजार से ज्यादा रकम

रायपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान गाड़ियों से बिना दस्तावेज के 50 हजार रुपए से ज्यादा बड़ी रकम नहीं ले जा सकेंगे. यही नहीं शराब का अवैध परिवहन, बिना दस्तावेज के प्रचार सामग्री, मतदाताओं को प्रभावित करने वाली संदिग्ध सामग्री व वस्तुओं का परिवहन, अनाधिकृत बैनर, पोस्टर प्रचार सामग्री, बिना अनुमति के प्रचार वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. इसके अलावा अधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाएगा. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध सामग्रियों के परिवहन रोकने और कार्यवाही को लेकर स्थैतिक निगरानी दल एवं फ्लाइंग स्क्वाड के सदस्यों का प्रशिक्षण रेडक्रॉस सभाकक्ष में आयोजित किया गया. इस प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बन्दे, संयुक्त कलेक्टर अभिलाषा पैकरा और मास्टर ट्रेनर डॉ. अजीत हुण्डेत एवं डॉ. राकेश डेरहगवे सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे. उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बन्दे ने स्थैतिक दल फ्लाइंग स्क्वाड दल को निष्पक्ष एवं पारदर्शी होकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चुनावी उद्देश्य से किसी प्रकार की अवैध सामग्री, अवैध 2राब की जब्ती बनाकर उचित कार्यवाही के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित करें. संपूर्ण जांच के दौरान वीडियोग्राफी कराने तथा संदिग्ध सामग्रियों की जब्ती बनाकर एफआईआर कर कोर्ट में मामला प्रस्तुत की जानी चाहिए.

छग सरकार का 58वां विभाग होगा सुशासन विभाग, अधिसूचना जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सुशासन विभाग की अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी गई है. यह विभाग छत्तीसगढ़ सरकार का 58वां विभाग होगा. बता दें कि साय सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में इस विभाग को मंजूरी मिली थी. राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य प्रशासन में पृथक रुप से एक नए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है. इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. नये विचारों एवं क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे. विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा. इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगे.

महिला वैज्ञानिक सम्मेलन व नवोन्मेषी मेला- शक्ति विज्ञान भारती और महिला अध्ययन केन्द्र रविशंकर विश्वविद्यालय का संयुक्त आयोजन

उल्लेखनीय कार्य के लिए नम्रता यदु को स्त्री प्रेरणा और दीप्ती सिंह को स्वशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया

रायपुर। महिलाओं का वैज्ञानिक समाजिक उत्तरदायित्व विषय में आयोजित सम्मेलन में महिला वैज्ञानिकों का गोल मेज सम्मेलन और नवोन्मेषी मेला का आयोजन किया गया! राउंड टेबल सम्मेलन के दौरान सभी पैनेलिस्ट ने समाज उपयोगी विषय पर अपने द्वारा किये गये वैज्ञानिक कार्य की प्रस्तुति दी। सम्मेलन में अतिथि पैने लिस्ट डॉ मौलश्री दुबे, मालिनी गुहा, डॉ प्रीतिका बैनर्जी ने सभी को बहुत प्रभावित किया! सभी विषयों पर प्रतिभागियों से प्राप्त विचारों का संकलन कर सारांश का प्रस्तुतीकरण किया गया!

निरंतर नयी तकनीक को आत्मसात करते हुए स्थानीय संसाधनों से उपयोगी उत्पाद निर्माण और सेवा का कार्य कर रही महिलाओं ने नवोन्मेषी मेला में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया , महिला वैज्ञानिकों का समूह के साथ इन महिलाओं का परस्पर संवाद हुआ जो इनके व्यवसाय की उत्तरोत्तर विकास में सहायक होगा! कार्यक्रम के दौरान सम्मेलन के उपलक्ष्य में डा प्रीति उपाध्याय का सम्मान दिव्यांग जनों के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले सेवा

कार्य हेतु किया गया! शक्ति स्थापना दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला को दिया जाने वाला स्त्री प्रेरणा सम्मान , छत्तीसगढ़ मशरूम की नम्रता यदु जी को और प्रतिभावान छात्रा के लिये दिए जाने वाला स्वशक्ति पुरस्कार कु दीप्ती सिंह को साइबर सुरक्षा में उनके शोध कार्य हेतु दिया गया!

इस पूरे आयोजन में कुलपति प्रो सच्चिदानंद शुक्ल, राष्ट्रीय शक्ति अध्यक्ष डॉ सुधा तिवारी वरिष्ठ वैज्ञानिक महात्मा गांधी ग्रामीण और औद्योगिक शोध केंद्र नागपुर और मुख्य वक्ता डॉ जे अमुधा वरिष्ठ वैज्ञानिक केन्द्रीय काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर ने अपने ऊर्जावान उद्बोधन से सबको उत्साहवर्धन किया! विश्वविद्यालय से प्रो रीता वेणुगोपाल,प्रो प्रियम्बदा श्रीवास्तव,प्रो नमिता ब्रम्हे,प्रो कविता ठाकुर,प्रो प्रीति सुरेश,प्रो आरती परगनिहा, डॉ अनुराधा, डॉ अनिक्षा का सक्रिय सहयोग रहा! छत्तीसगढ़ शक्ति की सभी शक्ति डॉ सूनंदा ढेंगें, प्रो स्वर्ण लता सराफ, डॉ स्मिता शर्मा,डॉ विनया अग्निहोत्री, प्रो अभया जोगलेकर, प्रो चंचलदीप कौर ,प्रो अंजली अवधिया, डॉ अरूणा चौबे, डॉ मंजरी बक्षी, प्रो रूपिंदर दीवान.प्रो रेणु महेश्वरी, डॉ दीप्ती झा , डॉ अंशिता गुप्ता, डॉ शुभ्रा तिवारी,डॉ मनीषा अग्रवाल, डॉ वर्षा वरवंडकर, डॉ इन्दू साधवानी, डॉ अर्पणा दुबे, श्रीमती श्वेता देवांगन, श्रीमती समिधा दुबे,श्रीमती सुलोचना तिवारी, श्रीमती मिथिलेश पाराशर,श्रीमती ममता सिंह का सक्रिय और प्रत्यक्ष सहयोग रहा वहीं संस्थापक सदस्य डॉ ऊषा दुबे का आशीर्वाद अप्रत्यक्ष के रूप से हर पल साथ रहा! राष्ट्रीय शक्ति से महासचिव वैद्य लीना जी बावड़ेकर सहित सभी कार्यकारिणी से मिली शुभकामनाएं ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया! कार्यक्रम का आयोजन प्रतिभागियों द्वारा जमा किये रजिस्ट्रेशन शुल्क, विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केन्द्र का आर्थिक सहयोग, कुछ सक्रिय शक्ति बहनों द्वारा संकलित सहयोग राशि से किया गया!

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.